



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2001/अग्रहायण 12, 1923

No. 319]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2001/AGRAHAYANA 12, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

प्रारंभिक जांच-परिणाम

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2001

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और यू.ए.ई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विट्रिफाइब/पोर्सिलेन टाइल्स के भारत में आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 37/1/2001-डीजीएडी.— 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. क्रियाविधि

1 जांच के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया गया है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के तहत मै. एस पी एल सिरामिक लि�0, मुंडका, बहादुरगढ़, हरियाणा, मै0 एच एंड आर जानसन इंडिया लि�0, महाराष्ट्र और मै0 मुरुदेश्वर सिरामिक लि�0, हुबली से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य और यूनाइटेड अरब अमीरात (यू.ए.ई) (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विट्रिफाइब/पोर्सिलेन टाइल्स के पाटन का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की है।

- (ii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध सामग्री के आयात के विरुद्ध जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने उक्त नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरूआत की कार्रवाई से पहले संबद्ध देशों के दूतावासों को कथित पाटन के संबंध में प्राप्त याचिका के बारे में अधिसूचित किया;
- (iii) प्राधिकारी ने दिनांक 6 अगस्त, 2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अधवा वहां से निर्यातित विट्रिफाइड/पोर्सिलेन टाइल्स, जिसका विवरण जांच शुरूआत अधिसूचना में दिया गया है (जिसे इसेक बाद संबद्ध वस्तु या विट्रिफाइड टाइल्स भी कहा गया है) और यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, की अनुसूची I के सीमाशुल्क अध्याय 69 के तहत वर्गीकृत है, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
- (iv) प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे) और उद्योग एशोसिएशनों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और नियम 6(2) के अनुसार उन्हें लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।
- (v) प्राधिकारी ने भारत में विट्रिफाइड टाइल्स के ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचार लिखित रूप में अवगत कराने का सुझाव दिया।
- (vi) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए विट्रिफाइड/पोर्सिलेन टाइल्स के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।
- (vii) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 6(3) के अनुसार याचिका के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध करवाई।
- (viii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य एवं यू.ए.ई के ज्ञात निर्यातकों, जैसीकि याचिकाकर्ता द्वारा इंगित किया गया है, को प्रश्नावली भेजी:

यू ए ई

1. अल खालीज सिरेमिक्स (पी एस सी)
2. आर ए के सिरेमिक्स

चीन जनवादी गणराज्य

1. फोशन शिवान डोंगपेंग सिरेमिक्स ग्रुप कं. लि०
2. ईगल ब्रांड होल्डिंग लि०
3. ननहाई सिटि किआओ-डोंग सिरेमिक्स कं. लि० (मोनालिसा)

(ix) मैसर्स आर ए के सिरेमिक्स और मै० अल खालीज सिरेमिक्स, यू ए ई और चीन जनवादी गणराज्य मै० गुआंगडोंग प्रोविन्स ताइ शान सिटि सप्लाई एंड मार्किटिंग को-आपरेटिव कंपनी, मै० लिहुआ सिरेमिक्स कंपनी लि०, ननहाई गुआंगडोंग और मै० गुआंगडोंग न्यू झोंग युआन सिरेमिक्स कंपनी से जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर प्राप्त हुआ था । अन्य किसी निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

(x) उपरोक्त नियम के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच के अधीन वर्स्तु के औद्योगिक उपभोक्ताओं और ऐसे प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी अवसर प्रदान किया था जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों के बारे में जांच से संबद्ध सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं । जांच शुरूआत अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित समय के भीतर जांच से संबंधित अपने निवेदन कर सकती है ।

(xi) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरूआत के बारे में सूचना दी गई थी और उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का जबाब निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें । ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित निर्यातक को भेजे गए पत्र, याचिका, प्रश्नावली की एक प्रति दूतावासों को भी भेजी गई थी ।

(xii) आवश्यक सूचना मंगाने के लिए नियम 6(4) के अनुसार भारत में विट्रिफाइड/पोर्सिलेन टाइल्स के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/थोक व्यापारियों को एक प्रश्नावली भेजी थी;

मै0 त्रिशला डिस्ट्रिब्यूटर्स, चेन्नई
 मै0 फोरचयून इंटरप्राइज, चेन्नई
 केंट सिरेमिक टाइल्स एंड कं. प्रा.लि., चेन्नई
 भारत मारबल, कोलकाता

सन अर्थ सिरेमिक्स लि0, अलीबाग
 एरिज ट्रैवल्स प्रा0लि0, नई दिल्ली
 सफाल वैसल एकिजम (प्रा0)लि0, केरल

कजारिया प्लस लि0, नई दिल्ली ।

तथापि, विट्रिफाइड/पोर्सिलेन टाइल्स के निम्नलिखित आयातकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उत्तर दिया गया था:-

- मै0 त्रिशला डिस्ट्रिब्यूटर्स
- मै0 निटको, मुंबई
- मै0 कजारिया सिरेमिक्स, नई दिल्ली
- मै0 साफा एल वैसल एकिजम प्रा0 लि0, कोच्ची
- मै0 चिनार सिरेमिक्स (इंडिया)प्रा0 लि0, मुंबई
- मै0 कैपसन्स सिरेमिक्स (इंडिया)प्रा0 लि0, मंबई

(xiii) याचिकाकर्ता से क्षति के बारे में अतिरिक्त व्यौरे मार्गें गए थे, जो प्रस्तुत कर दिए गए थे ।

(xiv) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षों के अगोपनीय अंश प्राधिकारी द्वारा रखी गयी सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ।

(xv) प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग की मौके पर जांच की गई ।

(xvi) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सामान्यःस्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और माल को बनाने तथा बेचने की लागत का हिसाब लगाने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का भी विश्लेषण किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(xvii) *** यह चिह्न इस अधिसूचना में याचिकाकर्ता/अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा भी ऐसा ही माना गया है ।

(xviii) यह जांच 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के लिए की गई थी ।

ख) याचिकाकर्ता के विधार

2. याचिकाकर्ता ने विट्रिफाइड टाइल्स के पाटन के विचारों तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं-

i) चीन से हुए निर्यातों के संबंध में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि दिनांक 31 मई, 2001 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं.28/2001 (एन टी) के तहत संशोधित नियमों के अनुसार, जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य के लिए परिकलित सामान्य मूल्य एक अच्छा संकेतक है, विशेष रूप से तब, जबकि कीमतों का निर्धारण कच्ची समाग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और याचिकाकर्ता के अपने उत्पादन और लागत आकड़ों के आधार पर किया जा रहा है और इस तथ्य को देखते हुए कि प्रौद्योगिकी या प्रचालन के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है ।

यू ए ई के संबंध में, याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का दावा बड़े उत्पादकों में से एक बड़े उत्पादक, अर्थात् मै0 आर ए के सिरेमिक्स, की कीमत सूची के आधार पर किया है ।

निर्यात कीमत का दावा याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध आयातों की सी आई एफ कीमत के आधार पर किया गया है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है ।

उपरोक्त के आधार पर, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दोनों संबद्ध देशों से बहुत अधिक पाटन मार्जिन है जो यह इंगित करता है कि भारत में संबद्ध वस्तु काफी कम और पाटित कीमत पर आ रही है । याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि इससे यह इंगित होता है कि निर्यातकों को न्यूनतम परिवर्तनीय लागत की वसूली भी नहीं हो रही है ।

ग) निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

निर्यातकों के विचार

3. मै0 आर ए के सिरेमिक्स, यू ए ई और अन्य निर्यातकों ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं-

सामान्य मूल्य

i) तथा कथित गैर बाध्यकारी कीमत सूची से यू ए ई से सामान्य मूल्य के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर विचार किया गया है जिसमें घरेलू बाजार में निष्पादित एक भी संविदा या की गई बिक्री का साक्ष्य नहीं हैं। कथित कीमत सूची सांकेतिक कीमतों का भी प्रमाणिक दस्तावेज नहीं हो सकती है। क्योंकि आर ए के सेरामिक्स, जो यू ए ई का मुख्य निर्यातक है, सभी संविदाओं का निष्पादन बातचीत द्वारा तय कीमत पर करता है। इस प्रकार विचार किया गया साक्ष्य न केवल निष्पादित संविदा के साक्ष्य के अभाव में कानूनन गलत है बल्कि भ्रामक और केवल अभिकथन है जिसे कानूनी कार्यवाहियों में सामान्य मूल्य के किसी साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता।

ii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आयात कीमतों से संबंधित सूचना, जो स्वीकार्यतः दिसंबर, 2000 तक के लिए उपलब्ध हैं का न्यायनिर्णयन है जिसे अविश्वनीय और अपर्याप्त पाया गया है। दूसरी ओर एक निजी आपरेटर, जिसने स्पष्ट तौर पर तोड़ मरोड़ कर भ्रामक सूचना प्रस्तुत की है, से प्राप्त गौण सूचना को शिकायतकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय भारत सरकार, से अधिक विश्वसनीय माना गया है। उपरोक्त को देखते हुए निर्यात कीमत संबंधी सूचना भी कानूनी कार्रवाइयों में स्वीकार किया जाने वाला प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है।

सार्थक अगोपनीयता

iii) याचिका कोई महत्वपूर्ण सूचना का सुराग नहीं देती है जो किसी भी मामले में भारत में प्रकाशित दस्तावेजों के जरिए सार्वजनिक सूचना हो। आर ए के सेरामिक्स के विचार से किसी उचित स्पष्टीकरण अथवा वाणिज्यिक अधिकार के बिना इस प्रकार की सूचना से संबंधित गोपनीयता जैसे कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि निर्यातकों को समुचित ढंग से मामला लड़ने में पंगु बना दिया है मांगी गई सूचना का ब्यौरा 1.9.2001 के उनके पत्र संख्या के एम/08-459/2001 में दी गई है।

iv) क्षति

इस प्रकार की किसी सूचना की जानकारी होने के उनके अधिकार के होते हुए भी आर ए के सिरामिक्स ने यह अनुरोध किया है कि क्षति का मामला न केवल बनाया गया है बल्कि यह ऐसे अभिकथनों से पूर्ण है जिनमें स्ती भर साक्ष्य नहीं है ।

क. स्पष्टतः मांग में लगातार वृद्धि हो रही है । याचिका में इसे सकल रूप से कम बताया गया है ताकि आयातों की न्यूनतम सीमा संबंधी जांच पूरी की जा सके । वस्तुतः मांग xxx% से बढ़कर xxx% हो गई है । एच एंड आर जान्सन (इंडिया)लिंगो ने अप्रैल 2000 की निदेशकों की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अगले कुछ वर्षों में मांग में xxx% से अधिक की वृद्धि होगी । उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है बिक्री कीमतों में भी समग्र रूप से स्थिरता और वृद्धि प्रदर्शित होती है हाल ही के प्रेस वक्तव्य में श्री के चन्द्रशेखर, महाप्रबंधक ने इस बात पर जोर दया है कि संबंधित उत्पाद की मांग वर्ष दर वर्ष xxx% से बढ़कर xxx% हो जाएगी (11.9.2001 का टाइम्स आफ इंडिया, पृष्ठ, 15) लाभों में बढ़ोत्तरी हो रही है और क्षति से संबंधित अन्य मापदंडों से बाजार हिस्से और क्षमता उपयोग में गिरावट जो कि पूर्णतः असत्य भी है और जिन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए कवरअप प्रचालनों से लिया गया है, को छोड़कर प्रगतिशील स्थिति का पता चलता है ।

ख. क्षमता उपयोग संबंधी आंकड़ों का आकलन सावधानी पूर्वक करना होता है जिनमें स्थापना, वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत, असमान्य तालाबंदी, बड़ी मरम्मत तथा अन्य अज्ञात कारणों से बन्दी आदि के समय को ध्यान में रखना होता है ।

ग. ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ताओं का स्पष्ट उद्देश्य या तो प्रमुख सूचना को छिपाकर अथवा न केवल शिकायतकर्ताओं बल्कि अन्य विनिर्माताओं के भी उपयोग का सही निर्धारण प्रदान न कर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रमित करना है । केवल इतना ही नहीं बल्कि शिकायतकर्ताओं ने स्वयं प्रमुख तथ्यों को भी छिपाया है अर्थात् एस पी एल ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि नए

विस्तार संयत्र ने 28 नवंबर, 2000 को प्रचालन शुरू किया और इसका उपयोग वर्ष के दौरान केवल 4 महीनों के लिए किया गया है, इसके अलावा बड़ी मरम्मत के कारण एस पी एल का संयत्र दो माह से अधिक समय के लिए बन्द रहा था। इसी प्रकार रिपोर्ट के अनुसार एच आर जान्सन्स का संयत्र भी लगभग दो महीने बंद रहा था जिसके कारण उन्हें, रन आफ किलन बिक्री करनी पड़ी थी जिसे जानबूझकर भ्रमित करने और गलत निष्कर्ष निकालने के लिए गढ़ा गया है।

घ. निर्यातकों के बाजार हिस्से में वृद्धि स्पष्टतः अर्थ व्यवस्था को खोले जाने के कारण हुई है जिसके बाद निर्यातकों को भी उस कीमत पर जो कि न केवल प्रतिस्पर्धी है बल्कि गैर पाठित भी है, बाजार हिस्से का उचित अंश प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार का स्पष्ट मामला यू ए ई से आयातों का बनता है।

ड. इस प्रकार यह अभिकथन कि कम क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में कमी क्षति का निर्णयक साक्ष्य है जबकि यूनिट कीमत प्राप्ति में वृद्धि होती है, उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री मूल्य और मात्रा तथा लाभों (प्रचालन कुशलता, उत्पादकता और प्रचालनात्मक लागत नियंत्रण के समान स्तर पर विचार करते हुए) में बेतहासा वृद्धि हो रही है, सत्य से परे है जैसा कि क्षति के विभिन्न कारकों के कंपनीवार विश्लेषण में तत्पश्चात व्यौरा दिया गया है। इससे शिकायतकर्ताओं के जरिए दिए गए अभिकथनों और भ्रामक अभ्यावेदनों का निष्कर्षतः खंडन होता है।

च. क्षति संबंधी संकेतकों के कंपनीबार विश्लेषण, जो कि प्रत्येक अलग-अलग कंपनी के लिए उनकी वार्षिक रिपोर्टों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित है, से यह सिद्ध होता है कि क्षति का मामला किसी भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के बिना बनाया गया है और इस प्रकार यह मामला इससे आगे वापस लिए जाने योग्य है।

V कारणात्मक संबंध

इसी प्रकार तथाकथित पाटन और आरोपित क्षति के बीच किसी साक्ष्य अथवा संबंध की पुष्टि भी नहीं हुई है जबकि केवल अभिकथनों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है कि इनमें कारणात्मक संबंध है,

क. भारतीय उद्योग ने अपनी प्रौद्योगिकी, जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रतिस्पर्धी हो सकती है, जिनकी निरन्तर मांग बनी रहती है, का उन्नयन करने के लिए आधुनिकीकरण में किसी निवेश को प्रदर्शित नहीं किया है।

ख. यह कम उत्पादकता, अकुशलता, परिचालन लागत में वृद्धि, उत्पाद संबंधी अङ्गचर्नों आदि का मामला है। जिससे लागत में वृद्धि और लाभ में कमी आई है, जिसका संबद्ध देशों से आरोपित निर्यातकों के साथ संबंध नहीं है।

ग. स्पष्टतया उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी बड़ी मात्रा में दोयम दर्जे का उत्पादन करती है जिससे कम प्राप्ति और अधिक घाटा होता है।

घ. घरेलू विनिर्माताओं की विपणन लागत काफी उच्च है जो अप्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादित दोयम दर्जे के माल की भारी मात्रा के साथ साथ कम प्राप्ति और अधिक घाटे के लिए जिम्मेवार है।

ड. याचिकाकर्ताओं ने स्वयं निदेशकों की रिपोर्ट, अध्यक्ष के दृष्टिकोण और/या निगमित चुनौतियों विश्लेषण इत्यादि के जरिए उत्पादन और बिक्री के घाटे और मार्जिन पर उसके परिणामी प्रभाव के लिए निम्नलिखित कारणों को स्वीकार किया है।

- प्रमुख संयंत्रों और उपकरणों के परिवर्धन और उन्नयन के चलते दो महीने के उत्पादन का घाटा
- गुजरात में आए भूंकप के कारण बिक्रियों में गिरावट।
 - डीजल जनरेशन सैटों की ओवरहालिंग के कारण उत्पादन संबंधी घाटा
 - कुछ इकाइयों को बिक्री कर में छूट की समाप्ति
 - विट्रिफाइड संयंत्र में घोर समस्याएं

- परिवालनात्मक लागत विशेष रूप से कच्ची सामग्री, बिजली और मजदूरी में वृद्धि जिससे मार्जिन में कमी आई ।
- उत्पाद शुल्क में कमी को बनाए रखने में असमर्थता ।
- लघु क्षेत्र से लगातार खतरा, कीमत में कटौती ।
- भारत में संगठित क्षेत्र के भीतर अनुचित प्रतिस्पर्धा ।

इस प्रकार, कारणात्मक संबंध घरेलू उद्योग के भीतर ही है जैसा कि साक्ष्य से पता चलता है और शिकायतकर्ताओं द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है जिसकी बजह संबद्ध देशों के निर्यातीं को बताना कल्पनातीत है ।

4. आयातकों के विचार

आयातकों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं-

- आयातित उत्पाद संबंधी सूधनाः याचिकाकर्ता जिस उत्पाद पर शुल्क की मांग कर रहा है, उस उत्पाद के संबंध में याचिका भ्रामक है । याचिका में उल्लिखित उत्पाद का विवरण निम्नानुसार है:

"पालिस की गई अथवा पालिश रहित फिनिश में अनइलेन्ड टाइल और ग्लेज्ड पोर्सिलेन/सिरेमिक टाइल दोनों में जल सोखने की क्षमता 3% से कम हो (आमतौर पर विट्रिफाइड टाइल/पोर्सिलेन टाइल के रूप में ज्ञात) ।

गलत रिमाइट उत्पाद विवरण से अन्य पार्टियां अपने हितों की रक्षा करने में अक्षम हो गई हैं ।

ii) याचिकाकर्ताओं की स्थिति

याचिकाकर्ताओं ने एस पी एल, जान्सन, मुरुदेश्वर, बेल ग्रेनाडटों, रेस्टाइल, स्पारटेक और सन अर्थ को संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों के रूप में शामिल किया है। तथापि जब स्वयं उत्पाद स्पष्ट नहीं है तब यह समझ में नहीं आता है कि याचिकाकर्ता ने कैसे अपनी स्थिति प्रमाणित की है। यदि सेरामिक टाइल्स वर्तमान जांच के दायरे में आती है तो निम्नलिखित कंपनियों भी देश में सेरामिक टाइल्स का उत्पादन कर रही हैं।

कजारिया सेरामिक्स

निटको

ओरिएंट सेरामिक्स

पेडर एंड पेडर

रीजेन्सी सेरामिक्स

बेल सेरामिक्स

अनन्तराज इंडिया

गोल कोइन सेरामिक्स

उक्त सूची भारत में सेरामिक टाइल्स उत्पादकों की अंतिम सूची नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन उत्पादकों को याचिका में शामिल क्यों नहीं किया गया। इन उत्पादकों द्वारा उत्पादित टाइल्स को उन टाइल्स से अलग नहीं रखा गया है जो वर्तमान जांच की विषय वस्तु हैं।

iii) याचिकाकर्ता उत्पाद का आयात कर रहे हैं

याचिकाकर्ता कंपनियों में से एक कंपनी स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात कर रही है। उक्त आयात किसी संबद्ध कंपनी के जरिए किए गए समझे जाते हैं किसी भी हालात में यह कंपनी घरेलू उद्योग का अंग नहीं बन सकती है।

iv. नियोत कीमत का आकलन करने के उद्देश्य से याचिकाकर्त्ताओं ने सेरेमिक मोजैक टाइल्स को शामिल किया है। इन मोजैक (लगभग 75 रुपए प्रति इकाई की कीमत) तथा विट्रिफाइड टाइल्स (लगभग 284 रुपए प्रति इकाई कीमत) के बीच बड़े कीमत अंतर की भी याचिकाकर्त्ताओं द्वारा अनदेखी की गयी है। इसका अर्थ सोने की चांदी के साथ जोड़ने के बराबर है। किसी भी हालत में याचिकाकर्त्ताओं को सेरेमिक मोजैक टाइलों के विरुद्ध पाटन की कोई शिकायत नहीं है। ऐसा मामला होने पर याचिकाकर्त्ता इसे निर्यात कीमत के आकलन के उद्देश्य से शामिल नहीं कर सकते हैं।

v. आंकड़ों के साथ छेड़छाड़: याचिका में संलग्न आयात सूचना से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना सेवा, मुम्बई द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना की प्रतिलिपि नहीं है, न ही याचिकाकर्त्ताओं ने याचिका में कहीं भी यह स्पष्ट किया है कि क्या उन्होंने आई बी आई एस से प्राप्त आंकड़ों में काट ^{स्पष्ट} छांट की है। आई बी आई, द्वारा दी गयी सूचना को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया गया है। ऐसे साक्ष्य को याचिकाकर्त्ताओं द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करते समय उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी।

vi. यू ए ई के निर्यातकों की कीमत सूची पर छूट: याचिकाकर्त्ता ने यू ए ई में सामान्य मूल्य का निर्धारण यू ए ई में कीमत सूची के आधार पर किया है। यदि याचिकाकर्त्ता यह दावा करते हैं कि कीमत सूची में दर्शाई गयी कीमतें प्रचलित कीमतों की प्रतिनिधि हैं तो हम प्राधिकारी से क्षति एवं क्षति मार्जिन के उद्देश्य से याचिकाकर्त्ता कम्पनियों की कीमत सूची पर निर्भर करने का अनुरोध करते हैं।

vii. निर्यात कीमत: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कम कीमतें दर्शने के उत्साह में याचिकाकर्ता निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए सेरेमिक मोजैक टाइल्स को भी शामिल कर लिया है। किसी भी कल्पना से मोजैक टाइलों और विट्रिफाइड टाइलों को एक समान नहीं माना जा सकता है। इसका अर्थ सोने को चांदी के साथ जोड़ने जैसा है। मोजैक टाइलों को निकालने के पश्चात् निर्यात कीमत की पुनः गणना किए जाने की आवश्यकता है।

viii. याचिका में क्षति संबंधी सभी मापदण्डों को कवर नहीं किया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि डब्ल्यू टी ओ विवाद निपटान निकाय ने यह निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ताओं को क्षति के सभी मापदण्डों के संबंध में सूचना देना अपेक्षित है। तथापि, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने उन मापदण्डों के संबंध में भी सूचना नहीं दी है जो कि प्रपत्र में दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने क्षति के निम्नलिखित मापदण्डों के संबंध में क्षति के साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं:

- (क) छूट गयी संविदाएं
- (ख) रोजगार
- (ग) बिक्री कीमतें
- (घ) कीमत कटौती
- (ङ.) कीमत में कमी
- (च) कीमत ह्रास

ix. क्षति का कारणात्मक संबंध: याचिकाकर्ताओं को कोई क्षति नहीं पहँची है। क्षति, यदि कोई है, तो वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के कारण नहीं है। क्षति के लिए बहुत से अन्य कारक उत्तरदायी हैं।

क. आयातों में कथित वृद्धि को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि टाइलों का आयात अप्रैल, 2000 से पहले आयातों की प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत था। इसके अतिरिक्त, आयातों की मांग, क्षमता तथा उत्पादन में हुई वृद्धि के साथ देखा जाना चाहिए। हालांकि आयात शून्य से बढ़कर 1.20 लाख वर्गमीटर तक हो गए हैं लेकिन याचिका के अनुसार भी भारतीय उत्पादों की बिक्री भी xxx लाख वर्गमीटर से बढ़कर xxx लाख तक पहुँच गयी है।

आयातों में हुई कथित वृद्धि का याचिकाकर्ताओं के सरेमिक मोजैक टाइलों, जो कि वर्तमान जांच की विषय वस्तु नहीं है, को शामिल करने के प्रयास के साथ देखा जाना चाहिए।

आयातों में वृद्धि अथवा मांग में उनके हिस्से का आकलन करने से पहले घरेलू उद्योग द्वारा ऐसे आयातों को छोड़ दिया जाना चाहिए।

ख. याचिकाकर्ताओं की बिक्री मात्रा और संबद्ध वस्तुओं के वास्तविक आयातों को देखते हुए दोनों देशों से हुए आयातों का बाजार हिस्सा 2 प्रतिशत से कम था। तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि मांग का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों को शामिल नहीं किया है। यदि इन बिक्रियों को जोड़ा जाता है तो दोनों देशों

से हुए आयातों का बाजार हिस्सा और भी कम होगा । देश में इस उत्पाद की मांग के संदर्भ में आयात न्यूनतम से भी कम था ।

ग यह कहना कल्पना करना ही है कि सबद्वे देशों से होने वाले आयातों का हिस्सा पहले ही अधिक अर्थात् 5.16 प्रतिशत है, याचिकाकर्त्ताओं द्वारा यह मान लिया गया है कि आयातों में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर से अधिक होगी । ऐसी अवधारणा का न तो कोई आधार है और न ही इसकी आवश्यकता है ।

घ संभवतः न्यूनतम से कम के लिए मापदण्ड हेतु मांग के संदर्भ में आयातों के हिस्से का प्रावधान भारतीय नियमों में विशिष्ट रूप से नहीं किया गया है । तथापि, अन्य देशों के नियम, जो कि काफी व्याख्याकारी और व्यापक हैं, में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आयातों की मात्रा का देश में उत्पाद की मांग यदि यह अलग अलग रूप से 1 प्रतिशत से कम और संचयी रूप से 3 प्रतिशत से कम है तो इसे न्यूनतम से भी कम माना जाना चाहिए ।

ड. यह बतलाना संगत होगा कि भारतीय नियमों में भी यह प्रावधान है कि क्षति के नाममात्र होने की स्थिति में जांच बंद कर दी जाए । इस मामले में क्षति नाम मात्र की है क्योंकि देश में मांग में आयातों का संपूर्ण हिस्सा अलग-अलग रूप से 1 प्रतिशत से कम और संचयी रूप से 3 प्रतिशत से कम है ।

च. याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह एक खुला गोपनीय तथ्य है,

हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस सूचना को गोपनीय रखने का दावा किया है।

छ. क्षमता उपयोग में कोई वास्तविक कमी नहीं हुई है। वास्तव में, जब उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई हो तब क्षमता उपयोग में कमी नहीं हो सकती है। क्षमता उपयोग में कथित गिरावट को सामान्य तौर पर उद्योग में और विशेषकर याचिकाकर्ताओं में क्षमता में हुई वृद्धि के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। चूंकि नई कंपनियोंने उत्पादन शुरू किया है इसलिए व चाहे पाटन हो या न हो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के तुरंत बाद ईष्टतम क्षमता उपयोग का सपना नहीं देख सकते हैं। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को क्षति के सभी मापदण्डों के संबंध में कंपनी वार आंकड़े प्रकट करने का निर्देश दिया जाए।

ज. याचिकाकर्ताओं की बिक्री मात्रा में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित होती है। बल्कि यह एक वृद्धि कर रहे और स्वस्थ उद्योग का सूचक है।

झ. एक याचिकाकर्ता कंपनी की उत्पादन लागत इसकी बिक्री कीमत से काफी कम है। यह कंपनी उल्लेखनीय लाभ कमा रही है। वास्तव में, इस कंपनी के लाभ में अत्यधिक सुधार प्रदर्शित हुआ है। इसका अर्थ यह है कि या तो अन्य उत्पादकों की उत्पादन लागत अधिक

है (जिसके लिए निर्यातक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता) या भारतीय उत्पादकों की बिक्री कोमर्स कम हैं (जिसके लिए भी निर्यातकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता)

एक याचिकाकर्ता कंपनी ने हाल ही में एक टाइल की शुरूआत की है (ब्राउड नाम "पोर्सेलानौ) जिसका कथित प्राप्ति उत्पाद से बहुत अच्छी हानि का दावा किया गया है : अंतिम उपभोक्ता के लिए इस टाइल की कीमत (80 रुपए प्रति वर्ग फुट एम आर पी) आयातित उत्पादन की पुनः बिक्री कीमत से काफी कम है ।

हाल की अवधि में कानूनी क्षमता बढ़ाह गयी है जो कि भारत में इस उत्पाद की माग से काफी अधिक है लगभग xxx लग्न मीट्र के आयात भारतीय उत्पादनों का लगभग xxx की सीमा तक की क्षमता का उपयोग करन से नहीं रोक सकत हैं । यह कम क्षमता उपयोग और इस प्रकार उत्पादन में घाट का कारण नहीं हो सकता है ।

ठ. याचिका गलत धारणाओं से भरी हुई हैं याचिकाकर्ताओं ने केवल ऐसे बयान ही दिए हैं जो कि पर्याप्त साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं किए गए हैं । कीमत कटौती, कीमत में कमी इत्यादि के संबंध में बयान केवल बयानबाजी ही है । यदि यह मान भी लिया जाता है कि पाटन हुआ है तो यह समझ में नहीं आता है कि जब आयात अभी शुरू ही हुए हैं तो याचिकाकर्ता कैसे "निरंतर पाटन" होने का उल्लेख कर सकते हैं । स्पष्टतया अन्य कारकों ने भारतीय उत्पादकों को घाटा उठाने पर मजबूर किया है ।

लाभ/घाटा याचिकाकर्त्ताओं ने यह दावा किया है कि उनके लाभ में कमी आयी है। इस कथन का अलग-अलग कंपनी के कार्य निष्पादन, वर्ग मीटर में आयातों की तुलना में 8.29 प्रतिशत (लाख वर्ग मीटर) क्षमता उपयोग में कमी तथा घरेलू उद्योग की बिक्रियों पर आयातों की मात्रा के प्रभाव के साथ जोड़कर दखल जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि पुरानी कंपनियां उचित लाभ के साथ चल रही हैं जबकि नए क्षमता उपयोग के कारण नई कंपनियों को घाटा हो सकता है। तथापि हमारा दृढ़भृत यह है कि किसी भी भागीदार कंपनी का घाटा नहीं हो रहा है। इनमें किसी भी मापदण्ड का पालन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

दूर्व म अत्यधिक लाभ पूर्व में भारतीय उत्पादक प्रवृत्त लाभ है तथा वास्तव में नवीन का विट्रिफाइल टाइलों के संबंध एवं दर वर्ष अच्छे लाभ हैं।

आयातकों तथा निर्यातकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

1. पात्रता

आयातकों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि याचिका की पात्रता नहीं है क्योंकि एस पी एल, जो कि एक याचिकाकर्त्ता है जिसन सीध अथवा सबद्ध कंपनियों के जरिए काफी मात्रा में कथित पाटित उत्पाद का आयात किया था, आयातकों के दाव का तथ्यों अथवा कानून के प्रावधानों के द्वारा समर्थन नहीं होता है। एस पी एल ने जांच की अवधि के दौरान

अथवा उससे पहले कथित स्रोतों से कथित पाटित उत्पादों का आयात नहीं किया है ।

कानून में यह स्पष्ट स्थिति है कि केवल उन उत्पादकों को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है जिन्होंने कथित उत्पादों का आयात किया है । चूंकि इस मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में एस पी एल को शामिल करना तथ्यों और कानून के द्वारा पूर्णतया समर्थित है । याचिकाकर्त्ताओं द्वारा विट्रिफाइड टाइलों के घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन दायर करने की स्थिति से संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारी का निर्धारण पूर्णतः न्यायोचित है और आयातकों के तर्क का कोई आधार नहीं है ।

2. सामान्य मूल्यः

यह आरोप लगाया गया है कि सामान्य मूल्य के संबंध में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य कानून सम्मत नहीं है क्योंकि ई के उत्पादकों में से एक उत्पादक की गैर-बाध्यकारी कीमत सूची पर भरासा किया गया है । आयातकों ने आग यह भी उल्लेख किया है कि साक्ष्य अनुपयुक्त है क्योंकि याचिकाकर्त्ताओं ने निष्पादित अनुबंधों का एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । आयातकों ने यह तर्क कि याचिकाकर्त्ताओं को निष्पादित अनुबंधों का साक्ष्य देने चाहिए थे परम्परा तथा कानूनी आधार पर एक हास्यारपद मान्यता है । अपनी खुद की स्वीकृति के अनुसार आयातक इस बात से अवगत हैं कि यू ए ई के उत्पादक अपनी वस्तुओं को मोल-

तोल की गई कीमतों पर बेचते हैं। यदि यह सच है तो घरेलू उद्योग से दोनों वाणिज्यिक कंपनियों के गोपनीय दस्तावेज प्राप्त करन की कानूनी अथवा व्यवहार में आशा नहीं की जा सकती है। इस संबंध में घरेलू उद्योग न निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान आवेदन प्रपत्र के भाग III के पैरा 1(क) की ओर दिलाया है जिसमें सुस्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि कीमत सूची को निर्यातक के घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य का उचित सूचक माना जा सकता है। शायद आयातकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कीमत सूची को जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए एक सर्वोत्तम प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में माना जाता है।

3. निर्यात कीमत

आयातकों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रम में डालने के लिए अविश्वसनीय और भ्रामक सूचना प्रस्तुत की है। इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि घरेलू उद्योग ने उन समस्त आंकड़ों, जिन्हें वे समुचित तरीके से संभवतः एकत्र कर सकते थे, को प्रदान कर यथासंभव पारदर्शी बने रहने के लिए समर्त प्रयास किए हैं। चूँकि अनेक आयातकों ने ऐसे कारणों से, जिन्हें उनके द्वारा ही स्पष्ट

किया जा सकता है, भिन्न-भिन्न शीर्षों के तहत विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, इसलिए हमें उपलब्ध आकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करना पड़ा। इसके अलावा आयातकों का यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वे सर्वप्रथम घरलू उद्याग द्वारा प्रस्तुत आकड़ों और जांच शुरूआत का औचित्यपूर्ण ठहरान के पर्याप्त साक्ष्य के रूप में घरलू उद्याग द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के संबंध में टिप्पणी का अधिकार प्राप्त करन से पूर्व अपने खुद के आयात संबंधी आकड़े प्रस्तुत करें। यह सच है कि अध्याय शीर्ष 69.14 में विचाराधीन उत्पाद से इतर अनेक उत्पाद आते हैं लेकिन यह कहना उतना ही गलत है कि हमने आयातों का अनुमान लगाते समय इन्हें शामिल कर लिया है। किसी भी मामले में आयातक यदि वे यह समझते हैं कि घरलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना गलत है तो वे निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपनी सूचना प्रदान करने के लिए अब बहुतर स्थिति में हैं। हम यह भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आयातकों ने उन आकड़ों को भी गोपनीय बनाए रखने के लिए अजीबोगरीब कारणों को चुना हैं जिन आकड़ों का हमारी याचिका के अगोपनीय अश का भाग समझा जाता है। स्पष्टतः वे यह नहीं चाहते हैं कि हम उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर कोई टिप्पणी करें।

4. क्षति

चूंकि आयातकों द्वारा किए गए अनुरोध इतने कपटपूर्ण और पूर्णतः झूठ हैं कि हम इस स्तर पर केवल तथ्या के मुद्दा पूछ ही उन पर सर्वप्रथम कार्रवाई करना उचित समझते हैं।

(i) इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आयातकों को इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि पाटनरोधी नियमों के तहत न्यूनतम मात्रा की जांच केवल कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में ही की जाती है न कि कुल मांग के अनुपात के रूप में। अतः घरेलू उद्योग के पास मांग को कम बताने का कोई कारण नहीं है जैसा कि आयातकों द्वारा सुझाव दिया गया है।

(ii) एच आर जे के निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लिखित भावी मांग से सामान्यतः समूच्च टाइल उद्योग का संकेत मिलता है। इसके अलावा, आयातकों ने अपनी सुविधानुसार निम्नलिखित पैरा की अनदेखी की है:

"तथापि, अगले वर्ष बाल एवं फ्लोर टाइल्स के आयात शुरू होने की संभावना और लघु क्षेत्र से मिलने वाली प्रतिस्पर्द्धा में बढ़ोतरी होने से बाजार के सामने कड़ी प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति आने की सभावना है।

आपकी कंपनी नए मूल्यवर्द्धित उत्पाद शुरू करके और अपने सेवा स्तरों में सुधार करके अपने संयंत्रों को लगातार उन्नत बनाकर इस स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर रही है।

हमारा विश्वास है कि अपनायी गयी और पहले ही कार्यान्वयित की जा चुकी कार्यनीतियों के कारण आपकी कंपनी के लिए भावी परिदृश्य उत्साहजनक रहता है।"

श्री के चन्द्रशेखर - महाप्रबंधक (बिक्री) द्वारा पोर्सलिनो (ग्लेज्ड पोरसिलीन टाइल्स) की शुरूआत के दौरान दिए गए प्रेस वक्तव्य में हमारी इस उम्मीद का हवाला मिलता है कि मांग में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लाभ में ही वृद्धि हो रही है।

(iii) एस पी एल के बिट्रिफाइड टाइल्स संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन मार्च, 2000 में शुरू किया न कि नवम्बर, 2000 में जैसा कि आयातकों द्वारा बताया गया है। आयातकों ने जानबूझकर यह वक्तव्य दिया है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए मामले की ग्राह्यता के खिलाफ पक्षपात कर सकें।

(iv) यह स्पष्ट किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने याधिकार्ता उद्योग की स्थिति का आकलन करने के लिए वस्तुतः सन अर्थ सिरामिक्स एंड स्पार्टेक की क्षमताओं को ध्यान में रखा था। इसके अलावा आयातकों के शेष अनुरोधों में भी एक और भ्रामक विवरण दिया

गया है। मधुसूदन सिरामिक्स और सन अर्थ सिरामिक्स की इकाई केवल सिरामिक ग्लेज्ड वाल/फ्लोर टाइलों का विनिर्माण करती है न कि विट्रिफाइड टाइलों का।

(v) वर्ष 1999-2000 के दौरान एस पी एल द्वारा विट्रिफाइड टाइलों की कोई बिक्री नहीं की गयी थी। इस प्रकार ये आंकड़े बिल्कुल भी तुलनीय नहीं हैं। इसके अलावा एस पी एल की प्रति मीटन प्राप्ति में बढ़ोतरी ग्लेज्ड टाइल क्षेत्र में मूल्यवर्द्धित उत्पादों के कारण हुई जबकि यह मामला केवल विट्रिफाइड टाइलों के संबंध में ही दायर किया गया है। इससे आयातको द्वारा दिए गए तर्क की असंगतता तथा शरारतपूर्णता स्पष्ट होती है।

(vi) जांच अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी मुख्यतः काढ़ी संयंत्र में स्थापित की गयी अतिरिक्त फ्लोर टाइल क्षमता के कारण हुई है। इस मामले में हमारा संबंध केवल विट्रिफाइड टाइलों से है।

(vii) संयंत्र/उपकरणों के रख-रखाव तथा उन्नयन के कारण विट्रिफाइड टाइलों के उत्पादन में संबंधित कोई घाटा नहीं हुआ था।

(viii) डिजल जेनरेटिंग सेटों की मरम्मत के कारण विट्रिफाइड टाइलों के उत्पादन में कोई घाटा नहीं हुआ है क्योंकि एस पी एल के पास विट्रिफाइड टाइलों की उस विशेष इकाई का चलान के लिए पर्याप्त अनुबंधी जनरेशन क्षमता थी।

(ix) गुजरात में जनवरी, 2001 के महीने में आए भूकम्प से विट्रिफाइड टाइलों के उत्पादन पर कार्ड प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि इसका संयंत्र हरियाणा में स्थित है। मुद्दों को भ्रामक बनाने के लिए आयातकर्ता ने इस तथ्य को जानबूझकर और सोच-समझकर अनदेखी की है।

(x) जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि विट्रिफाइड टाइलों का उत्पादन मार्च, 2000 में शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता न गलती से उत्पादन की शुरूआत नवम्बर 2000 में दर्शाई है। एस ^{पी} एल द्वारा यह तथ्यों का निरूपण है और उनके द्वारा तथ्यों को छुपाया नहीं गया है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

(xi) वर्ष 2001-02 की प्रथम तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि ^{जल्दी} तिमाही की तुलना में कुल आय में वृद्धि न कवल विट्रिफाइड टाइलों की बिक्री से हुयी थी बल्कि नवम्बर 2000 में काड़ी में चालू किए गए फ्लार टाइलों के नए संयंत्र से लगभग 600 लाख रुपए की फ्लार टाइलों की बिक्री से भी हुयी थी।

(xii) शिकायतकर्ता न अनेक बार उन आकड़ों का उल्लेख किया है जो विट्रिफाइड टाइलों के उत्पादन और बिक्री से संबंधित नहीं हैं आर इनसे एस ^{पी} एल संयन्त्रों में वाले और फ्लार टाइलों के उत्पादन के संबंध में भ्रम उत्पन्न होता है। अतः उपरोक्त के मद्देनजर लाभों के

समायोजन की कोई प्रासंगिकता नहीं है । एस पी एल के निर्यातों में वृद्धि वाल और फ्लोर टाइलों के निर्यातों में हुई वृद्धि के कारण हुई है ।

(xiii) उपरोक्त स यह स्पष्ट होता है कि आयातकों द्वारा दिए गए समर्त तर्क गलत निरूपण, तथ्यों, आंकड़ों और पाठनरोधी कानून की पूर्णतः गलत व्याख्या पर आधारित हैं और इसलिए

विट्रिफाइड टाइलों के प्रयोजन से जांच अवधि के संबंध में इनका कोई वजूद नहीं है ।

(xiv) यह कंपनी विट्रिफाइड टाइलों के अलावा वाल और फ्लोर टाइलों का विनिर्माण भी करती है। इस कंपनी के देश के विभिन्न भागों में चार संयंत्र हैं। निदेशकों की रिपोर्ट में दर्शायी

गयी उपलब्धि संयुक्त उपलब्धि है न कि यह उपलब्धि अनिवार्यतः विट्रिफाइड टाइलों के

संबंध में। विट्रिफाइड टाइलों के संबंध में उक्त आकड़े पहले ही अलग से प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(xv) कंपनी द्वारा पिछले दो वर्षों में क्षमता का लगातार सर्वद्वन्द्वन किया जा रहा है और इसलिए स्थापित क्षमता में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(xvi) क्षमताओं में वृद्धि इसलिए की जाती है ताकि खासकर पूँजी गहन उद्योग में बड़े प्रमाण पर किफायत की जा सके। इसके अलावा तुलन पत्र में उल्लिखित कुल क्षमता की तुलना

नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें वाल, फ्लोर और विट्रिफाइड टाइलं शामिल हैं और इस प्रकार यह कोई संकेतक नहीं है ।

(xvii) यह स्वीकार्य तथ्य है कि थाणे स्थित फैक्ट्री इस कंपनी की सबसे पुरानी फैक्ट्री है और यह प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद मिक्स दोनों रूपों में पुरानी है । थाणे स्थित फैक्ट्री द्वारा विट्रिफाइड टाइलों का विनिर्माण नहीं किया जाता है ।

(xviii) पाटनराधी नियमों में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे घरेलू उद्योग, जिसका घरेलू उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा बनता है, द्वारा या उसकी ओर से उचित आवेदन दायर करना होता है । यह तथ्य कि कुछेक कंपनियों ने आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया है, कानूनी अथवा आर्थिक दृष्टि से कोई अहमियत नहीं रखता है । याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी आवेदन को वैध आवेदन बनाने के लिए अपेक्षित शर्तों को सावधानी पूर्वक पूरा किया गया है ।

(xix) याचिकाकर्ताओं द्वारा टाइलों का उत्पादन करने के लिए उत्कृष्ट इतालवी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह दावा पूंजीगत व्यय से भी स्पष्ट होता है । भारतीय उद्योग द्वारा लगातार निवेश और अपनी विनिर्माण क्षमताओं का उन्नयन किया जा रहा है । एच आर जे एच आर जे ने पिछले चार वर्षों में 187 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है । एच आर जे की विट्रिफाइड टाइल्स कंपनी की स्थापना विश्व की सर्वोत्तम उपलब्ध संयंत्र एवं मशीनरी

एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके की गयी है। विट्रिफाइड टाइलों के लिए इतालवी प्रौद्योगिकी को निर्विवाद रूप से विश्व की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी के रूप में स्वीकार किया जाता है। एच आर जे के संयंत्र की आपूर्ति इटली के एस ए सी एम आई, जो विश्व में विट्रिफाइड टाइल संयंत्र का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, द्वारा की गयी है।

(xx) एच आर जे द्वारा विनिर्मित टाइलों का व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया है जिसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि एच आर जे को सिंगापुर से पी एस बी प्रमाणन और इटली से वेलोन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। अतः हमारी टाइलों को घटिया कहना पूर्णतः भ्रामक है। वस्तुतः एच आर जे द्वारा 70 प्रतिशत उच्च गुणवत्ता की विट्रिफाइड टाइलों का विनिर्माण किया जाता है। एच आर जे के उत्पाद उत्तने ही उत्तम किस्म के हैं जितने की विश्व में उत्पाद उपलब्ध हैं और अब यह इनका निर्यात यूरोप, मध्य पूर्व और सुदूर-पूर्व के देशों को करता है।

(xxi) याचिकाकर्ता (एच आर जे) ने 'रन ऑफ क्लिन' आधार पर कोई बिक्री नहीं की है। इस आरोप पर कड़ी आपत्ति की जाती है और यह आरोप मानहानि का मामला चलाने के भी योग्य है। एच आर जे द्वारा 'रन ऑन क्लिन' बिक्रियों के बारे में उक्त अनुरोध में किए गए दावे के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(xxii) पोर्सिलैनै के रूप में एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बेची जा रही टाइलैं

वस्तुतः विट्रिफाइड पोरसिलिन टाइले हैं जोकि आयातकों के दाव के प्रतिकूल है और जिनकी उन्होंने पूर्णतः अनदेखी की है ।

(xxiii) आयातकों का यह तर्क अजीबोगरीब और चौकाने वाला है कि उपभोक्ताओं के हित में

शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए । यू ए ई के एक प्रमुख निर्यातक अर्थात् आएके ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा भारत को तीसरी और चौथी गुणवत्ता की टाइलों की आपूर्ति की जा रही है । तीसरी और चौथी गुणवत्ता के उत्पादों से उपभोक्ताओं के हितों का संबद्धन नहीं हो सकता है । अधिकांश आयात चौथी गुणवत्ता के उत्पादों में हुए हैं जैसा कि आर ए सिरामिक्स द्वारा अपने अनुरोध में स्वीकार किया गया है और इसलिए आयातकों द्वारा अनन्य/उत्कृष्ट उत्पादों के आयात का झूठा दावा कर भ्रमित किया जा रहा है ।

ड. उठाए गए मुद्दों की जांच

6. निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए उपर्युक्त निवेदनों की प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक जांच की गई है, उन पर विचार किया गया है और इस अधिसूचना में उपर्युक्त स्थानों पर उन पर विचार किया गया है, जहां तक नियमों के अनुसार वे संगत हैं और जहां तक इस मामले पर वे प्रभाव डालते हैं ।

च. विधाराधीन उत्पाद तथा जांच का दायरा

7. इस याचिका में दावाकृत विधाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पालिश की गई या बिना पालिश के तैयार बिना चमकीली तथा चमकदार पोर्सलेन/सैरेमिक टाइलें हैं जो 3 % से कम जल-अवशोषण वाली हों (जिन्हें आम तौर पर विट्रिफाइड टाइल/पोर्सलेन टाइल कहा जाता है) । चमकदार तथा बिना चमकीली (विट्रिफाइड/पोर्सलेन टाइलों) का उपयोग मुख्यतः फर्शों तथा दीवारों को आच्छादित करने में किया जाता है । इन टाइलों का उपयोग भवनों, घरों, रेस्टोरेंटों, सिनेमाहॉलों, हवाई अड्डों, स्विमिंग पूल्स, रेलवे स्टेशनों आदि में होता है ।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सभी प्रकार की बिना चमकीली टाइलें अध्याय शीर्ष 69.07 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं । तथापि, बिना चमकीली टाइलों का आयात पोर्सलेन की अन्य वस्तुओं के रूप में अध्याय शीर्ष 69.14 के अंतर्गत भी किया जाता है । इसके अलावा, चमकीली पोर्सलेन टाइलों का आयात अध्याय शीर्ष 69.14 के अंतर्गत विभिन्न विनिर्देशनों के साथ किया जाता है जैसे जी.पी. टाइल्स, पोर्सलेन टाइल्स, ग्रेस पोर्स लेनाटो टाइल्स, पोर्सलेन विट्रिफाइड टाइल्स आदि । यह भी कहा गया है कि अध्याय शीर्ष 69.14

के तहत आयात की जाने वाली चमकीली पोर्सलेन टाइलें विशेषताओं, प्रयोग, कार्यों वितरण, माध्यम आदि की दृष्टि से अध्याय शीर्ष 69.07 के अंतर्गत आने वाली बिना चमकदार टाइलों के साथ स्थानापन्न योग्य हैं। याचिकाकर्त्ताओं ने यह भी कहा है कि कई आयातकों द्वारा चमकीली पोर्सलेन टाइलों का वर्गीकरण गलत ढंग से अध्याय शीर्ष 69.14 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। ये उत्पाद सही ढंग से चमकीली टाइलों के रूप में अध्याय शीर्ष 69.08 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। इसलिए याचिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस बात का विचार किए बिना कि किस वर्गीकरण के तहत इन उत्पादों का आयात किया जा रहा है, विचाराधीन उत्पाद के विरुद्ध जांच शुरू को जाए। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतित हैं और वर्तमान जांच क्षेत्र के लिए किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

तथापि, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को यह स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक अधिसूचना की व्याख्या में औद्योगिक टाइलें कवर नहीं होतीं, चाहे भले वे विट्रिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा ही उत्पादित की गई हों। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि औद्योगिक विट्रिफाइड टाइलों को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा जाए क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के साथ उनकी प्रतिस्पर्द्धा नहीं है। उपलब्ध सामग्री की जांच के आधार पर प्राधिकारी घरेलू उद्योग के दावे को स्वीकार करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि विट्रिफाइड औद्योगिक टाइलें जांच के दायरे में नहीं आती हैं।

छ. समान वस्तु

8(क) पाटनरोधी नियमों के नियम 2(घ) में दिया गया है कि "समान वस्तु" का अर्थ है, एक ऐसी वस्तु जो जांच के अधीन उत्पाद से हर तरह से मिलती जुलती हो या उसके

समान हो और ऐसी वस्तु के अभाव में, ऐसी अन्य वस्तु, जिसके गुण जांच के अधीन वस्तुओं के गुणों से बिल्कुल मिलते जुलते हों।

(ख) याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं इसलिए याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयातित विट्रिफाइड/पोर्सलेन टाइलों को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान वस्तुएं माना जाए।

(ग) निर्यातकों/आयातकों ने तर्क दिया है कि उनके द्वारा आयातित टाइलें भिन्न किस्म की हैं। लेकिन, यह दर्शाने के लिए उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि आयातित टाइलें घरेलू तौर पर उत्पादित टाइलों के स्थान पर तकनीकी रूप से अथवा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विट्रिफाइड टाइलों की विशेषताएं संबद्ध देशों से आयातित टाइलों की विशेषताओं के समान हैं। वितरण के माध्यम, अंतिम उपयोग आदि भी यह दर्शाते हैं कि आयातित टाइलें विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

(घ) इसके महेनजर, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयात की जा रही विट्रिफाइड/पोर्सलेन टाइलें नियमों के अर्थ में समान वस्तु हैं।

(ज) घरेलू उद्योग

१. यह याचिका मै0 एसपीएल लिमितेड, मै0 एच एण्ड आर जानसन इण्डिया लिमितेड तथा मै0 मुरुदेहवार सैरामिक लिमितेड द्वारा दायर की गई हैं। याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन में वर्गमीटर के रूप में उनका लगभग 60 % हिस्सा बनता है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्त्ताओं का आवेदन दायर करने का आधार नहीं बनता है क्योंकि पात्रता मानदण्ड निर्धारित करने के लिए टाइलों के कई अन्य

उत्पादकों के उत्पादन को हिसाब में नहीं लिया गया है। आयातकों ने अपने दावे के समर्थन में टाइलों के कुछ उत्पादकों के विशेष रूप से नाम दिए हैं। प्राधिकारी ने इस संबंध में आयातकों द्वारा किए गए दावों तथा रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य की जांच की है। आयातकों द्वारा बतलाए गए उत्पादक विट्रिफाइड टाइलों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं और इसलिए पात्रता के प्रयोजन के लिए उनके उत्पादन को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि टाइलों के ऐसे अनेक लघु उत्पादक हैं जिनके उत्पादन को भी हिसाब में नहीं लिया गया है। प्राधिकारी एतद्वारा स्पष्ट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के तहत प्राधिकारी को केवल विचाराधीन उत्पाद को ही हिसाब में लेना जरुरी है। इस मामले में, जांच का दायरा केवल विट्रिफाइड टाइलों तक ही सीमित है और देश में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन के आधार पर पात्रता मानदण्ड पर्याप्त रूप से पूरा होता है।

झ. पाटन

सामान्य मूल्य

10. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातिक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो, या
- (ii) जहां निर्यातिक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातिक देश या क्षेत्र

के स्वदेशी बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की समुचित तुलना नहीं हो सकती हो, तो सामान्य मूल्य या तो:-

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य ; या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत जिसमें प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि की गई हो ।

पाटनरोधी नियमों में गैर-बाजारी अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए 15.07.1999 तथा 31.05.2001 को अधिसूचित संशोधनों के द्वारा अलग से प्रावधान किए गए हैं ।

चीन जनवादी गणराज्य

11. प्राधिकारी ने धारा 9 क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारण के प्रयोजन से सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी । लेकिन चीन से किसी भी निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली के प्रपत्र में प्राधिकारी को उत्तर नहीं भेजा और पूर्ण सूचना नहीं भेजी है । इसलिए, प्राधिकारी मानते हैं कि चीन से किसी भी निर्यातक के नियमों में की गई अपेक्षानुसार प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है । घरेलू उद्योग ने चीन में सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर प्रस्तुत की है । चीन के निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया है ।

निर्यात कीमत:

12. चीन से किसी भी निर्यातक ने निर्यात मात्रा तथा मूल्यों के संबंध में पूर्ण जानकारी मुहैया कराने के लिए प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। चीन से संबद्ध वस्तुओं का बड़ी मात्रा में आयात हाल ही में शुरू हुआ है और वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपर्युक्त को देखते हुए आंकड़े सीमाशुल्क दैनिक सूचियों के आधार पर गौण स्रोतों से संकलित किए गए हैं। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर मालभाड़े, समुद्री बीमे, कमीशन, पत्तन पर रखरखाव आदि के लिए उनमें आगे समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन

12.क सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमों में यथाविहित सिद्धान्तों की व्याख्या नियमों के अनुबंध I में की गई है। चीन के लिए परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर प्रति मी0 टन बैठता है। इसी प्रकार के मापदण्डों के आधार पर और इसी प्रकार के समायोजनों की अनुमति देते हुए निवल निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति मी0 टन आती है। चीन से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के लिए डम्पिंग मार्जिन निर्यात कीमत का 247 % आता है।

यू.ए.ई.:

13. मै0 आर ए के सैरामिक्स को छोड़कर अन्य किसी भी निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली के प्रपत्र में सूचना नहीं दी है।

जहां तक मै0 आर ए के सैरामिक्स का संबंध है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उक्त निर्यातक द्वारा दी गई सूचना ज्ञात नहीं हो सकती है क्योंकि निर्यातक द्वारा दिए गए प्रश्नावली के उत्तर में समुचित अगोपनीय अंश का अभाव है। यह तर्क दिया गया है कि निर्यातक ने परिशिष्ट 4 से 6 और 8 से 10 जैसे निर्णायक परिशिष्टों का सूचीबद्ध रूप अथवा अगोपनीय अंश देने की भी परवाह नहीं की है। फलस्वरूप, निर्यातक द्वारा दावा किए गए कीमत ढांचे, कुल बिक्री, समायोजनों आदि के बारे में घरेलू उद्योग को टिप्पणी करने से निर्यातक ने जानबूझ कर बंधित किया है। इसलिए, समुचित अगोपनीय अंश के अभाव में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः निर्यातक के प्रत्युत्तर को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर देने की जरूरत है जैसाकि पूर्वाक्त मामले में किया गया था जब तक वे अपने कानूनी दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं।

यह उल्लेख किया गया है कि भारत को बेचे गए माडल यू.ए.ई. में तथा अन्य देशों को बेचे जाने वाले माडलों से भिन्न हैं। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे कोई विनिर्देशन मुहैया नहीं कराए गए हैं जिससे तकनीकी मानदण्डों के आधार पर यह तय किया जा सके कि उक्त माडल किस प्रकार भिन्न हैं। इसलिए जानकारी अपने प्रयोजन के विश्लेषणों तथा कथनों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। भिन्नता की वजह से लागत में जो अंतर आया है, उसके आधार पर ही भौतिक अंतर के समायोजन की अनुमति दी जाती है।

केवल पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए ही किसी उत्पाद के वर्गीकृण के लिए ऐसे बयान, अटकलबाजी तथा अनुमान पर्याप्त नहीं हैं। यह तर्क भी दिया गया है कि निर्यातक द्वारा किए गए दावे परस्पर विरोधी हैं। यदि बिक्रियां अंतिम उपभोक्ताओं को की गई हैं तो मात्रात्मक छूट का दावा करने का प्रश्न कहां उठता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्यातक ने बिक्री प्रबंधों का ब्यौरा नहीं दिया है जैसाकि पैरा "ग" के अंतर्गत अपेक्षित है। इसलिए, निर्यातक द्वारा दी गई जानकारी को अपूर्ण एवं अविश्वसनीय मानते हुए अस्वीकृत किए जाने की जरूरत है।

घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि पाटनरोधी नियमों तथा परिपाटी के अनुसार गुणवत्ता के लिए समायोजन की अनुमति तभी दी जा सकती है, अगर उसे भौतिक विशेषताओं के द्वारा दर्शाया जा सकता हो। ऐसे दावों को विभेदी मूल्य वसूली के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती है। निर्यातक ने वास्तविक अग्रिम ऋणों के ब्यौरे नहीं दिए हैं और उसने घरेलू बिक्रियों तथा अन्य देशों को की गई बिक्रियों को एक साथ मिला दिया है।

घरेलू उद्योग ने यह तर्क भी दिया है कि आर ए के द्वारा अपनाई गई लागत-विधि अत्यन्त आपत्तिजनक है और पुष्टि के योग्य नहीं है क्योंकि ग्रेड का विचार किए बिना उत्पाद की लागत एक जैसी है। यह सुझाव देना हास्यास्पद है कि उत्पाद की लागत बिक्री-वसूली पर निर्भर करती है चाहे उसका ग्रेड कोई भी हो। इसके अलावा, आर ए ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि उसके पास कोई लागत-गणना की पद्धति नहीं है जब जरूरत होती है तो "संकेतिक लागत" परिकलित की जाती है। इसके साथ कहते हैं कि प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए उत्पादन लागत के आंकड़ों तथा लेखा-

का प्रयोग करते हुए सामान्य तौर पर निर्धारित लागत आंकड़ों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।

14. उपर्युक्त मुद्दों की प्राधिकारी ने सावधानीपूर्वक जांच की है। यह देखा गया है कि अगोपनीय अंश में अपेक्षित जानकारी नहीं दी गई है जैसाकि घरेलू उद्योग ने बतलाया है। प्राधिकारी का यह मत है कि अधिकांश परिशिष्टों के अगोपनीय सारांश प्रस्तुत नहीं किए जाने से प्रावधानों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। संबद्ध वस्तुओं की विभिन्न किस्मों के श्रेणीकरण का आधार भी नहीं बतलाया गया है जिससे पाटन तथा क्षति मार्जिन विश्लेषण की उचित तुलनाकरण कठिन हो गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक ने विभिन्न ग्रेड की टाइलों के लिए अलग-अलग लागतों पर विचार करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिए हैं।

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी के पास सामान्य मूल्य/निर्धारण आर ए के तथा यू ए ई के अन्य सभी निर्यातकों के लिए रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

15. उपर्युक्त के आधार पर चीन से सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन 247 % बैठता है जबकि यूएई से सभी निर्यातकों के लिए डम्पिंग मार्जिन निर्यात कीमत का 148 % बैठता है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

16. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के कार्मिकों द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर किया

गया है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए निम्नलिखित मानदण्डों का विश्लेषण किया गया है:

बिक्री की मात्रा तथा मूल्यः

घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि विट्रिफाइड टाइल उद्योग भारत में बहुत पुराना नहीं है। गत वित्तीय वर्ष में जब उद्योग घाटे से उबरने की उम्मीद कर रहा था, तभी संबद्ध देशों से पाठन के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों की तुलना में बिक्री की मात्रा में कुछ सुधार तथा बिक्री कीमतों में मामूलीवृद्धि के बावजूद इसका घाटा बढ़ गया। प्राधिकारी पाते हैं कि बिक्री की मात्रा में तथा बिक्री कीमत में भी पिछले दो वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। इकाई मूल्य वसूली में भी जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 % की वृद्धि हुई है लेकिन इन वृद्धियों का आकलन उन अतिरिक्त क्षमताओं के संदर्भ में करना होगा जो इस अवधि के दौरान सृजित की गई और डिमेंग की मात्रा, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की तुलना में पहुंच कीमत तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश से हुई आय के संदर्भ में करना होगा।

चीन तथा यूरेश से हुए आयातों का बाजार हिस्सा

संबद्ध वस्तुओं के आयात आंकड़ों की जांच से पता चलेगा कि संबद्ध देशों अर्थात् चीन तथा यूरेश से आयात (कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के शून्य स्तर से बढ़कर जांच अवधि के दौरान लगभग 71 % हो गए।

वर्ष	संबद्ध देशों से आयात(वर्गमीटर)	कुल आयात	% हिस्सा
1998-99	0.00	121.00	0.00 %
1999-2000	0.00	8.22	0.00 %
अप्रैल 2000-मार्च	119570.00	169246.70	70.65 %
2001			

प्राधिकारी को मालूम है कि वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में संबद्ध वस्तुओं का आयात प्रतिबंधित था। इसलिए उसने जांच अवधि के अन्दर तुलनात्मक प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का निश्चय किया। आयात आंकड़ों की जांच से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयात में जांच अवधि में बाद में छः महीने की अवधि में प्रथम छः महीनों की तुलना में जोरदार वृद्धि हुई है। जहां जांच अवधि के पूर्वार्द्ध में संबद्ध देशों से आयात कुल आयात का केवल 6.42 % हुआ, वहीं जांच अवधि के उत्तरार्द्ध में यह हिस्सा 93.58 % बनता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयात जांच अवधि में एक खतरनाक वृद्धि का रुख दर्शाते हैं। जांच अवधि के उत्तरार्द्ध में पूर्वार्द्ध की तुलना में आयात में पन्द्रह गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात खुलने के प्रथम वर्ष की तुलना में कुल आयातों में भी इसी प्रकार का रुख रहा लेकिन यह परिवर्तन इतना जोरदार और

उल्लेखनीय नहीं है जैसा कि संबद्ध देशों के मामलों में जांच अवधि में ही आयातों की वृद्धि-दर घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का एक पर्याप्त संकेतक है। इस तथ्य को संबद्धदेशों से असामान्य रूप से कम कीमतों के संदर्भ में भी देखा गया है।

विवरण	पूर्वार्द्ध		उत्तरार्द्ध		2000-2001 के लिए कुल	
	मात्रा(वर्गमी०में)	मूल्य(रु०में)	मात्रा(वर्गमी०में)	मूल्य(रु०में)	मात्रा(वर्गमी०में)	मूल्य(रु०में)
संबद्ध देश	7681	2870228	111889	23275570	119570	26145798
अन्य देश	12999	3709046	36677	11722513	49677	15431559
सकल योग	20681	6579274	148567	34998083	169247	41577357

आयातों का % हिस्सा

संबद्ध देशों से	6.42 %	10.98 %	93.58 %	89.02 %	100.00 %	100.00 %
अन्य देशों से	26.17 %	24.04 %	73.83 %	75.96 %	100.00 %	100.00 %
कुल	12.22 %	15.82 %	87.78 %	84.18 %	100.00 %	100.00 %

संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा (कुल मांग का %)

प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों, साचिकाकर्त्ताओं तथा अन्य उत्पादकों समेत घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्रियों को जोड़ते हुए देश में इसकी कुल मांग परिकलित की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के आयात ने मात्र एक वर्ष की अल्प अवधि में कुल मांग का 3.66 % बाजार हिस्सा प्राप्त कर लिया। इस बात पर विचार करते हुए कि विट्रिफाइड टाइलें उपभोक्ता सामान के स्वरूप की हैं बाजार में इसका 3.66 % हिस्सा स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा और भी अधिक हो सकता है क्योंकि यह अनुमान केवल चुनिंदा पत्तनों से लगाया गया है।

वर्ष	संबद्ध देशों से आयात(वर्ग मी०)	कुल मांग	% हिस्सा
1998-1999	0.00	1884870	0.00 %
1999-2000	0.00	2372081	0.00 %
अप्रैल 2000/मार्च 2001	119570	3262558	3.66 %

उत्पादन तथा कम क्षमता उपयोग

घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि की दर अच्छी रही है और परम्परागत फर्श तथा दीवारों पर इसका उपयोग बढ़ रहा है। यह भी दावा किया गया है कि बढ़ते हुए बाजार के बावजूद संबद्ध देशों द्वारा बेतहाशा पाटन की वजह से उनके घाटे में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने पाया है कि वर्षों से घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वर्गमीटर के हिसाब से बढ़ा है। तथापि, जैसा कि दौरा करने वाले दल ने नोट किया है, विट्रिफाइड टाइलों जैसे उत्पाद के मामले में क्षति के एक कारक के रूप में क्षमता उपयोग का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। यह पाया गया है कि एक विशिष्ट अवधि के दौरान उत्पादित टाइलों के आकार पर निर्भर करते हुए क्षमता उपयोग में काफी अन्तर होगा। इस प्रकार, टाइलों जैसे उत्पाद के लिए, जहां विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हुए स्थापित क्षमता भी परिवर्तनीय है, क्षमता उपयोग को उद्योग को प्रभावित करने वाले एक वैध संकेतक के रूप में नहीं माना जा रहा है।

विक्री मूल्य/लाभप्रदता

घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन हाल ही में काफी पूँजी लगाकर शुरू किया है और पिछले दो-तीन साल से अपने आप को स्थिर करने का प्रयास कर रहा था। इतने बड़े पैमाने पर पाटन की घटना से घरेलू उद्योग को बहुत क्षति हुई है और ऐसे समय में उसके घाटे में वृद्धि हो गई है जब घरेलू उद्योग को घाटे की स्थिति से उबरने की उम्मीद थी। हालांकि प्राधिकारी को समूचे घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच करनी जरूरी थी, फिर भी प्राधिकारी ने अलग-अलग इकाइयों के काये निष्पादन को काफी विस्तृत जांच की है। यह नोट किया गया है कि एम सी एल, जिसे मामूली लाभ ही रहा है, वह भी अपनी पूँजी की लागत पर व्याज वसूलने में असमर्थ रहा

है और जांच अवधि में विट्रिफाइड टाइलों के मामले में समग्र रूप से उनके प्रति इकाई लाभ में भी पिछली अवधि की तुलना में कमी आई है।

वर्ष	बिक्री कीमत(लाख रु० में)	बिक्री की लागत(लाख रु० में)	लाभ/इकाई
1998-1999	***	***	***
1999-2000	***	***	***
अप्रैल 2000- मार्च 2001	***	***	***

कीमत में कटौती

यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु की बिक्री पर की जाने वाली निवल वसूली पर चीन तथा यूएई द्वारा की जाने वाली डिमिंग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। याचिकाकर्ताओं को अपना बाजार हिस्सा बरकरार रखने के लिए चीन तथा यूएई से संबद्ध वस्तु के कम कीमत देने आयातों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ी। पाटित आयातों की पहुंच कीमत से भी यह संकेत मिला कि कीमतों में भारी कटौती हो रही है।

	चीन (रु० में)	यूएई (रु० में)
स्वदेशी उत्पाद का औसत बिक्री मूल्य(उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	100.00	100.00
आयातित उत्पाद की पहुंच कीमत(सीआईएफ + मूल सीमा शुल्क)	42.56	65.63
कीमत में कटौती की मात्रा	57.44	34.37

कम कीमत पर बिक्री

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस दावे की भी जांच की है कि विभिन्न इकाइयों द्वारा किए गए निवेश पर उन्हें घाटा हो रहा है अथवा अत्यन्त कम प्राप्ति हो रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति का आकलन करने के लिए कम कीमतों पर बिक्री एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एक

विस्तृत विश्लेषण यह दर्शाता है कि सम्पूर्ण घरेलू उद्योग को विट्रिफाइड टाइल्स की अपनी बिक्रियों पर घाटा हुआ है जबकि इसका एक घटक अपने निवेश पर उचित लाभ प्राप्त नहीं कर सका है। प्राधिकारी ने उचित एन आई पी का हिसाब लगाया है और पहुंच कीमत के साथ उसकी तुलना की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिक्री कीमतों में कितनी कमी की गई है।

मालसूची तथा स्टॉक

स्टॉक के विश्लेषण से यह पता चलता है कि वर्ष 2000-2001 के अंत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में स्टॉक में लगभग 14 % तक की वृद्धि हुई है।

कम कीमत पर बिक्री, कीमत में कटौती की मात्रा, बाजार हिस्से में परिवर्तन जैसे कारक और लाभप्रदता के मानदण्ड स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन कारण घरेलू उद्योग को जांच अधिक में वास्तविक क्षति हुई है।

ट. कारणात्मक संबंधः

17. यह पता लगाने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया है:-

(i) चीन तथा यूरोप से पाटित मूल्यों पर संबद्ध वस्तुओं के प्रचुर आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतों अलाभकर स्तर तक कम करने के लिए बाध्य किया जिससे भारतीय बाजार में कीमत कटौती की स्थिति पैदा हो गई।

(ii) चीन तथा यूरोप से आयातों ने भारतीय बाजार में इस उत्पाद की कीमतों को इतना दबा दिया कि घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से अपनी पूरी उत्पादन लागत वसूल करने तथा उचित लाभ अर्जित करने से वंचित हो गया।

ठ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्देः

18. सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है, जिससे याचिकाकर्ता कंपनियों को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा को फिर से बहाल करना है जो कि देश के सामान्य हित में है। तथापि पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेषकर तब, जब पाटनरोधी शुल्क की लेवी उस राशि तक ही सीमित कर दी जाए जो याचिकाकर्ता कंपनियों को हुए नुकसान को कम करने

के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से याण्टन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, याचिकाकर्ता कंपनियों का हांस रुकेगा और सम्बद्ध सामग्री के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

19. याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षति को समाप्त करने के लिए जरुरी पाटनरोधी शुल्क की मात्रा मालूम करने के लिए प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर पर इस्टतम उत्पादन लागत पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए भारत में सम्बद्ध सामग्री की क्षतिरक्षित कीमत पर भरोसा किया है।

20. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते समय पाटन से भिन्न ऐसे किन्हीं कारकों, यदि कोई हों, पर विचार नहीं किया गया है, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो।

21. प्राधिकारी किसी विशेष स्रोत से किए जाने वाले आयातों या आपूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश नहीं करते हैं और इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को संबद्ध सामग्री की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ड. निष्कर्ष:

22. उपरोक्त पर विचार करते हुए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

क) यूएई लथा चीन के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर दिया गया है जिससे पाटन हुआ है।

ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ग) यह क्षति संबद्ध देशों के आयातों से सामूहिक रूप से हुई है।

23. यह आवश्यक समझा गया है कि अंतिम निर्धारण होने तक यू.ए.ई. तथा चीन के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर अनन्तिम रूप से पाटनरोधी जारी लगाया जाए।

24. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के बाबत या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने का विचार किया है, जो यदि लगाया जाता है, तो उससे घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो

जाएगी । इस प्रयोजन के लिए आयातों के औसत पहुंच मूल्य की तुलना याचिकाकर्ता कंपनी के जांच अवधि के लिए निर्धारित क्षतिरहित बिक्री मूल्य के साथ की गई थी । जहां अंतर डम्पिंग मार्जिन से कम था, वहां डम्पिंग मार्जिन से कम शुल्क की सिफारिश की गई है । यह आवश्यक समझा गया है कि आगे जांच तथा अंतिम निर्धारण होने तक यूएई तथा चीन के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर अनन्तिम रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

25. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि यू.ए.ई. तथा चीन के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर अनन्तिम शुल्क लगाया जाए । यह पाटनरोधी शुल्क 13-62 अमरीकी डालर प्रति वर्गमीटर तथा आयातों की पहुंच कीमत के बीच का अंतर होगा, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से चीन तथा यूएई के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर लागू होगा ।

26. इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे ।

27. आगे की प्रक्रिया:

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टीयों से इन निष्कर्षों के बारे में टिप्पणियां अमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम निष्कर्षों में विचार किया जाएगा ।

(ख) प्राधिकारी द्वारा मिर्यातकर्ता, आयातकर्ता, याचिकाकर्ता तथा अन्य इसी हितबद्ध पार्टीयों को अलग से लिखा जा रहा है, वे इस पत्र के जारी होने की तारीख से 40 दिनों के अन्दर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कर सकती है ।

- (ग) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों को मौखिक अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे जिन्हें उसके बाद लिखित में प्रस्तुत करना होगा ।
- (घ) प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक उस पर आगे जांच करेंगे ।
- (ङ.) अन्तिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे ।

एल. वी. सराम्भणि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

Preliminary Findings

New Delhi, the 3rd December, 2001

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports into India of Vitrified/Porcelain Tiles originating in or exported from China PR and UAE.

No. 37/1/2001-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:
 - i. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the Rules, received written application from M/s SPL Ceramics Ltd., Mundka, Bahadurgarh, Haryana, M/s H&R Johnson India Ltd, Maharashtra and M/s Murudeshwar Ceramics Ltd, Hubli have filed a petition alleging dumping of Vitrified/Porcelain tiles (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Peoples' Republic of China and United

Arab Emirates (UAE) (hereinafter also referred to as subject countries).

- ii. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the petitioner, decided to initiate investigations against imports of subject material from the subject countries. The Authority notified the Embassies of the subject countries about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the Rules;
- iii. The Authority issued a public notice dated 6th August, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of Vitrified/Porcelain tiles of the description given in the initiation notification (hereinafter also referred to as the subject goods or vitrified tiles) and classified under custom Chapter 69 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975, originating in or exported from the subject countries;
- iv. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known exporters (whose details were made available by the petitioner) and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with rule 6(2);
- v. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known importers of Vitrified tiles in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;
- vi. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (C.B.E.C.) to arrange details of imports of Vitrified/Porcelain tiles for the past three years, including the period of investigations.

vii. The Authority provided a copy of the non-confidential petition to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with rules 6(3) supra;

viii. The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information, to the known exporters from China PR and UAE as indicated by the petitioner, as mentioned below in accordance with the Rule 6(4):-

UAE

1. Al Khaleej Ceramics (PSC)
- 2.. RAK Ceramics

CHINA PR

1. Foshan Shiwan Dongpeng Ceramic Group Co. Ltd.
2. Eagle Brand Holding Limited
3. Nanhai City Qiaodong Ceramics Co. Ltd. (Monalisa)

ix. Response to the initiation notification was received from M/s RAK Ceramics and M/s Al Khaleej Ceramics, UAE and M/s Guangdong Province Tai Shan City Supply & Marketing Cooperative Company, M/s Lihua Ceramics Company Ltd., Nanhai Guangdong and M/s Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Company from China PR. None of the other exporters responded.

x. As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority has also provided opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causal link. It was also mentioned in the initiation notification that any other interested party may also make

its submissions relevant to the investigation within the time limit set out.

- xi. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporter was also sent to the Embassies, along with a list of known exporters/producers;
- xii. A questionnaire was sent to the following known importers/ wholesale dealers of Vitrified/Porcelain tiles in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4):

M/s Trishla Distributors, Chennai
 M/s Fortune Enterprises, Chennai
 Kent Ceramic Tiles & Co. Pvt Ltd, Chennai
 Bharat Marble, Kolkata
 Sun Earth Ceramics Ltd., Alibagh
 Aries Travels Pvt. Ltd., New Delhi
 Safaal Wasel Exim (P) Ltd., Kerala
 Kajaria Plus Ltd., New Delhi

The response was, however, filed by the following importers of Vitrified/Porcelain tiles as per prescribed proforma: -

- ◆ M/s Trishla Distributors
- ◆ M/s NITCO, Mumbai
- ◆ M/s Kajaria Ceramics, New Delhi
- ◆ M/s Safa Al Wasel Exim Pvt. Ltd., Kochi
- ◆ M/s Chinar Ceramics(India) Pvt. Ltd., Mumbai
- ◆ M/s Kapsons Ceramics (India) Pvt. Ltd., Mumbai

- iii. Additional details regarding injury was sought from the petitioner, which were also furnished;
- iv. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- xiv. The Authority conducted spot verification of the domestic industry to the extent considered necessary.
- xv. The cost of production of the domestic industry was also analysed to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) based on the information furnished by petitioner so as to ascertain if anti-dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to domestic industry.
- xvi. this notification represents information furnished by petitioner/other interested parties on confidential basis so considered by the Authority under the Rules.
- xvii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2000 to 31st March, 2001.

B. PETITIONERS' VIEWS

2. The petitioner had expressed the following views in the petition with regard to dumping of Vitrified tiles and the injury to domestic industry as a consequence thereof:

i) DUMPING:

In respect of exports from China, petitioner stated that according to the amended rules under Custom Notification No.28/2001(N.T.) dated 31st May, 2001, the Constructed

Normal Value is a good indicator for Normal Value in China PR for the purpose of initiation, particularly as the prices are being determined on the basis of international prices of raw materials and petitioner's own production and costing data, and in view of the fact that there are no significant differences in the level of technology or operation.

With regard to UAE, petitioner claimed Normal Value on the basis of price list of one of the major producers, i.e. M/s RAK Ceramics.

The Export Price had been claimed on the basis of imports figures available with the petitioner with their CIF values and adjustments were claimed with regard to ocean freight, marine insurance, inland transport, port handling and port charges.

On the basis of above, the petitioner claimed that there is a huge dumping margin from both the subject countries which indicates that subject goods are coming into India at extremely low and dumped price. Petitioner further claimed that this indicates that the exporters are not even recovering the nominal variable cost.

C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

VIEWS OF EXPORTERS:

3. M/s RAK Ceramics, UAE and other exporters have given the following comments:
 - i. **Normal Value**

The *prima facie* evidence of normal value from UAE has been considered from a so-called non-binding price list which does not evidence even a single concluded contract

or a sale in the Domestic Market. The alleged price list cannot be an authentic document of evidence of even the indicative prices since RAK Ceramics which is the major exporter from UAE concludes all contracts at a negotiated price. The evidence thus considered is not only bad in law for the lack of evidence of concluded contract but is also misleading and only a assertion which cannot be held as an evidence of normal value in the legal proceedings.

ii. Export Prices

The information on the import prices of the Director of Commercial Intelligence and Statistics, Ministry of Commerce and Industry which are admittedly available upto December, 2000 have been adjudged, unreliable and insufficient. On the other hand the secondary information from a private operator who has apparently supplied a doctored information after manipulation has been relied upon by the complainants as more reliable than the Government of India, Director General of Commercial Intelligence and Statistics. In view of the above, the information on Export prices also is *prima facie* not an evidence to be recognized in the legal proceedings.

iii. Meaningful Non-confidential

The petition does not give any clue to vital information which in any case in India are public information through the published accounts. In view of RAK Ceramics, in a proceeding like this confidentiality on such information without any reasonable explanation or commercial proprietary is purposely to ensure that the exporters are handicapped to contest the case properly.

iv. Injury

Notwithstanding their right to access such an information RAK Ceramics has submitted that the case on injury has

also not only been made but is only full of assertions without an iota of proof of evidence.

a. Apparently the demand has been consistently increasing. It has been grossly understated in the petition to only satisfy the *de minimus* test of Imports. The demand in fact has been increasing by ***% to ***%. H&R Johnson (India) Ltd., in its Directors Report of April 2000 has clearly admitted the increase in demand by above ***% for the next few years. The production has been continuously increasing and the employment generation has also increased. The Sales Prices in absolute terms has also shown stability and growth. In a recent press statement, Mr. K. Chandrashekhar, General Manager has emphasized that the demand of the product concerned will grow by ***% to ***% year on year (Times of India 11.9.2001 page 15). Profits are increasing and other parameters of injury apparently show a position of progress and strength except that decline in market share and capacity utilization which are also grossly untrue and have been derived from cover-up operations to mislead the Designated Authority.

b. Capacity Utilization statistics have to be carefully worked out considering the time of installation, commencement of commercial production, unusual shut down, closures for major overhauling and other unforeseen reasons etc.

c. It appears that the complainants have with a clear purpose to mislead the Designated Authority, either concealed Vital Information or has not given the correct determination of the Utilization of not only the complainants but also the other manufacturers. Not only this, the complainants themselves concealed major facts i.e., SPL did not disclose the fact that the new expansion plant came into operation on 28th November, 2000 and has

been used only 4 months during the year. Further SPL's plant was closed for over 2 months due to major overhauling. Similarly HR Johnson's plant also was inoperative as per reports for about 2 months due to which they had to go for a Run of Kiln Sale. Apparently, the submissions are designed to deliberately mislead and derive wrong conclusions.

d. The increase in the market share of Exporters is apparently due to opening up of the economy allowing the exporters also to take up a reasonable part of the market share at a price which is not only competitive but also non-dumped which apparently is the case of Imports from UAE.

e. Thus the assertions that lower capacity utilisation and loss of market share is the conclusive proof of Injury, while the unit price realisation increases, production capacity utilization, sales value & volume and profits (considering same levels of operations, efficiency, productivity and operations, efficiency, productivity and operational cost controls) keeps growing leaps and bounds is a misnomer, as detailed herein after, in the detailed company-wise analysis of various factors of injury. These conclusively rebut the assertions and misleading presentations made through the complainants.

f. The company-wise analysis of injury indicators based on their annual reports and other available evidence for each individual company conclusively prove that the case of injury has not at all been made out at all even *prima facie* and as such the case deserves to be withdrawn forthwith.

v. Causal Link

Similarly, no evidence or link has also been established between the so-called dumping and alleged injury whereas only on the basis of simple assertions the petitioners have tried to conclude that there is a causal link.

- a. The Indian industry has neither shown investment in modernization in order to upgrade technology which could be competitive for producing goods that are in continuous demand.
- b. There is a case of lower productivity, inefficiencies, increased operational costs, product bottlenecks etc., leading to higher cost and decreased profits which has no relationship with the alleged exports from subject countries.
- c. Apparently the technology used generates high volumes of sub-standard production which leads to lower realization and higher losses.
- d. The domestic manufacturers have very high marketing cost which along with high volume of sub standard goods produced through the non-competitive technology results into low realization and higher losses.
- e. Petitioners themselves have through Directors Reports, Chairman's overview and/ or corporate challenges, analysis etc. admitted the following reasons for loss of production and sales and resultant impacts on margins:
 - ◆ Modification and up-gradation of major plants and equipment's leading to loss in 2 months production.
 - ◆ Earthquake in Gujarat causing Sales decline.

- ◆ Loss of production due to overhauling of Diesel Generation sets.
- ◆ End of Sales Tax exemption to some units.
- ◆ Teething problems in vitrified plant.
- ◆ Rise in operational cost particularly Raw materials, Power and Labour leading to shrink in margins.
- ◆ Inability to retain the reduction in excise duty
- ◆ Continuous threat, price undercutting from the small scale sector.
- ◆ Unfair competition within the organized sector in India.

The causal link, therefore, is within the domestic industry itself as evidenced and admitted by the complaints themselves, which by no stretch of imagination could be attributed to the exports of subject countries.

VIEWS OF IMPORTERS:

4. The importers have given the following comments:
 - i) **Imported product information:** The petition is confusing with regard to the product on which the petitioner is seeking duties. The description of the product mentioned in the petition is as under :

“Unglazed tiles in polished or unpolished finish and Glazed Porcelain/Ceramic tiles both with less than 3% water absorption (commonly known as vitrified tiles/Porcelain Tiles)”.

The ill-defined product description has severely handicapped the other parties from defending their interests.

ii) **Standing of the petitioners :** The petitioners have included SPL, Johnson, Murudeshwar, Bell Granito, Restile, Spartek and Sun Earth as the Indian producers of the subject goods. However, when the product itself is not clear, it is not understood how the petitioners have established their standing. In case “ceramic tiles” are within the scope of the present investigations, the following companies also produce ceramic tiles in the Country:

Kajaria Ceramics
 NITCO
 Orient Ceramics
 Pedder & Pedder
 Regency Ceramics
 Bell Ceramics
 Anantraj Industries
 Gold Coin Ceramics

The above is not an exhaustive list of ceramic tiles producers in India. It is not clear why these producers have not been included in the petition. The tiles produced by these producers have not been segregated from the tiles which are the subject matter of the present investigations.

iii. **Petitioners are importing the product:**

One of the petitioner companies itself is importing the subject product. The imports are understood to be through an affiliate company. In any event, this company cannot form part of domestic industry.

iv. The petitioners have included **ceramic mosaic tiles** for the purpose of export price calculations. Even the huge price difference between these mosaic (priced at around Rs. 75 per unit) and vitrified tiles (priced at around Rs. 284 per unit) has been ignored by the petitioners. This amounts to

... combining gold with silver. In any event, the petitioners have no complaint of dumping against ceramic mosaic tiles. Such being the case, the petitioner cannot include this for the purpose of export price calculations.

- v. **Tampering of the data:** From the import information enclosed in the petition, it is evident that the information enclosed by the petitioners is not a copy of the information provided by International Business Information Service, Mumbai, nor have the petitioners clarified anywhere in the petition whether the data received by them from IBIS has been filtered by them. The information provided by IBIS has been used as an evidence. Such evidence could not have been tampered by the petitioners while providing the same to the Designated Authority.
- vi. **Discounts on price list of UAE exporters:** The petitioner have determined normal value in UAE on the basis of price lists in UAE. In case the petitioners claim that prices quoted in the price lists are representative of the prevailing prices, then we request the Designated Authority to kindly verify the price lists of the petitioner companies for the purpose of injury and injury margin.

Export price: As stated earlier, the petitioner have, in their zeal to show lower prices, included even CERAMIC MOSAIC TILES for calculating export price. By no stretch of imagination mosaic tiles and vitrified tiles be treated as similar. This tantamount to combining gold with silver. The export price is required to be computed again after removing mosaic tiles.

Petition does not deal with all injury parameters: It is noteworthy that WTO Dispute Settlement Body has held that petitioners are required to give information in respect of all injury parameters. However, it is found that the petitioners have not given information in respect of even

those parameters which have been listed in proforma. The petitioners have not provided evidence of injury in respect of following injury parameters:

- a) Lost contracts
- b) Employment
- c) Selling prices
- d) Price undercutting
- e) Price suppression
- f) Price depression

ix. **Injury and causal link:** There is no injury to the petitioners. The injury, if any, is not due to the alleged dumping of subject goods from subject countries. These are several other factors responsible for injury.

a. Alleged increase in imports must be seen alongwith the fact that the import of tiles was under restricted list of imports prior to April, 2000. Further, the imports must be seen alongwith the phenomenal increase in demand, capacity and production. While the imports grew from nil to 1.20 lac sq. meters, the sales of the Indian Producers grew from *** lacs sq.meters to *** lacs even as per petition.

The alleged increase in imports must be seen alongwith the attempts of the petitioners to include CERAMIC MOSAIC TILES, not a subject matter of present investigations. Such imports must be excluded by the domestic industry before increase in imports or their share in demand is assessed.

b. Market share of imports from the two countries was less than 2%, considering the sales volumes of the petitioners and actual imports of subject goods. However, it is noteworthy that the petitioners have not included sales of other Indian Producers for demand assessment. When these sales are added, the market share of imports from the

two countries in demand would be even lower. The imports were de-minimus with reference to demand of the product in the country.

- c. It is presumptive to state that the share of imports from the subject countries is already as high as 5.16%, it has been presumed by the petitioners that the rate of increase in imports would be higher than the rate of increase in demand. There is neither a basis nor warrant for such conjecture.
- d. That share of imports in terms of demand as criteria for de-minimis may not have been specifically provided in the Indian Rules. However, rules of other countries, which are quite elaborate and comprehensive, clearly have a provision that volume of imports shall be considered as de-minimus in case the same is less than 1% individually and less than 3% collectively of demand of the product in the country.
- e. It is relevant to point out that even Indian Rules provide for termination of investigations in case the injury is negligible. The injury in this case is negligible since the entire share of imports in demand in the country is less than 1% individually and less than 3% collectively.
- f. Production of the petitioner companies has phenomenally increased. This is an open secret, even when the petitioners have attempted to claim this information confidential.
- g. There is no actual decline in capacity utilization. In fact, there cannot be decline in capacity utilization when the production has phenomenally increased. The alleged decline in capacity utilization must be seen along with capacity additions in the industry in general and petitioners in particular. Since new companies have commenced production, they cannot naturally dream of optimum

utilization immediately after commercial production – whether dumping or no dumping. We request the Designated Authority to direct the petitioners to disclose company-wise data on all injury parameters.

- h. Sales volumes of the petitioners shows phenomenal increase. It rather shows sign of a growing and healthy industry.
- i. Cost of production of one of the petitioner company is much lower than its selling price. This company is making significant profits. In fact, the profits of this company have shown very significant improvement. This implies that either other producers are having higher cost of production (for which the exporters can not be blamed) or selling prices of Indian Producers is lower (for which again the exporters cannot be blamed).
- j. One of the petitioner companies has very recently introduced a tile (brand name “ Porselano”) which is claimed to be far superior to the alleged dumped product. The price of this tile to the end consumer (Rs. 80 sq.ft. MRP) is far lower than the resale price of imported product.
- k. There are significant capacity additions in the recent period, which is much more than the demand of the product in India. Imports of about *** sq meters cannot prevent the Indian producers from not utilizing capacity to the extent of about ***. This cannot be a reason for lower capacity utilization and hence loss of production.
- l. **Petition is full of conjectures:** The petitioners have merely made statements, unsubstantiated with sufficient evidence. The statements on price undercutting, suppression, etc. are mere statements. Even if it is assumed that dumping took place, it is not understood how

the petitioners could refer to continued dumping”, even when the imports have started now. Evidently, other factors have forced the Indian producers to make losses.

- m. **Profit/loss:** The petitioners have claimed that their profits have declined. The statement must be seen alongwith individual company's performance, decline in capacity utilization by 8.29% (*** Lacs Sq. Meter) against imports of *** sq. meters and effect of the volume of imports on the sales of the domestic industry. The fact is that older companies are running with reasonable profitability, while the newer companies could be making losses due to obvious lower capacity utilization. However, we strongly believe that none of the participating companies should be making losses. None of these parameters can be linked to dumping.
- x. **Huge profits in Past:** The Indian Producers were earlier making huge profits in the past. In fact, Naveen has been posting higher profits year after year in respect of vitrified tiles.

D. COMMENTS OF THE DOMESTIC INDUSTRY ON THE ISSUES RAISED BY IMPORTERS AND EXPORTERS

5. (i) Standing:

It has been stated by the importers that the petition lacks standing as SPL who is one of the petitioners, had either directly or through related companies imported the alleged dumped products in significant quantities. The contention of the importers is not supported either by the facts or the provisions of law. SPL has not imported the alleged dumped products from the alleged sources during the period of investigation nor prior to that. It is the unambiguous

position in law that only those producers who have imported the alleged products may be excluded from the definition of domestic industry. That not being the case, the inclusion of SPL as a part of the domestic industry is perfectly supported by the facts and the law. The determination by the Designated Authority with regard to the standing of the petitioners to file the application on behalf of the domestic producers of vitrified tiles is fully justified and the argument of the importers has no merit whatsoever.

(ii) Normal Value:

It has been alleged that the *prima facie* evidence with regard to the Normal Value is bad in law as reliance has been placed on the non-binding price list of one of the UAE producers. The importers further go on to say that the evidence is bad as the petitioners have not supplied even a single evidence of a concluded contract. The argument of the importers that the petitioners should have produced evidence of concluded contracts is a preposterous proposition on ethical as well legal grounds. The importers are, as per their own admission, aware that UAE producers sell their goods at negotiated prices. If this is true, then the domestic industry cannot be expected legally or in practice to get the confidential documents of two commercial entities. In this connection, the domestic industry has drawn the attention of the Designated Authority to Para 1 (a) of Part III of the Application Proforma wherein it has been unambiguously mentioned that price list can be a reasonable indicator of the Normal Value in the home market of the exporters. Perhaps the importers are not aware that the price list is considered as an excellent *prima facie* evidence to justify the initiation of an investigation.

(iii) Export Price:

It has been alleged by the importers that the domestic industry has submitted unreliable and 'doctored' information to mislead the Designated Authority. In this connection, attention of the Designated Authority has been drawn to the fact that the domestic industry has made all attempts to be as transparent as possible by giving all the data which they could possibly collect in a reasonable manner. Since a large number of importers have imported the product under consideration under different headings for reasons which can only be explained by them, we had to carry out a detailed analysis of the available data. Nonetheless, it is the duty and obligation of the importers to first provide their own import data before they acquire the right to comment upon the data furnished by the domestic industry and accepted by the Designated Authority as sufficient evidence to justify the initiation of an investigation. It is true that Chapter Heading 69.14 has many other products than the product under consideration but it is equally untrue to say that we have included the same while making the estimates of the imports. In any case, the importers are in a much better position to now give their information to the Designated Authority, if they consider that the information given by the domestic industry is inaccurate. We would also like to submit that the importers have for strange reasons chosen to keep confidential even those figures which are supposed to be a part of the non-confidential version of our petition. Obviously, they do not want us to comment on the propositions made by them.

(iv) Injury:

Since the submissions made by the importers are so outrageously mischievous and outrightly false, we consider it appropriate to first deal with them only on the issues of facts at this stage:

- a) In this connection, it may be mentioned that the importers need to be aware of the fact that under the Anti-dumping Rules, the test of de minimus volume is done only as a percent of the total imports and not as a proportion of the total demand. Therefore, there is no reason whatsoever for the domestic industry to underestimate the demand as suggested by the importers.
- b) In Directors' Report of HRJ, the future demand mentioned is generally indicative of the entire tile industry. Moreover, the importers have conveniently overlooked the following para:

“However, expected opening up of imports of Wall & Floor Tiles next year and increased competition from small scale sector is likely to keep the market fiercely competitive.

Your Company has been preparing itself to face this scenario by continuously upgrading its plants, introducing new value added products and improving its service levels.

We are confident that with the strategies adopted and already implemented, the future outlook for your company remains encouraging.”

The Press Statement of Mr. K. Chandrasekhar – General Manager (Sales) made during the launch of “Porselano” (Glazed Porcelain tiles) referred to our

expectation that the demand should grow. However, it does not follow that profits are also increasing.

- c) SPL's Vitrified Tiles plant commenced commercial production in March 2000 and not November 2000, as stated by the importers. The importers have deliberately made this statement to bias the Designated Authority against the merits of the case made by the domestic industry.
- d) It may be clarified that the domestic industry had indeed taken into account the capacities of Sun Earth Ceramics & Spartek for calculation of standing of the petitioner industry. Further, the importers, as the rest of their submissions, have made yet another misleading statement. The unit of Madhusudan Ceramics and Sun Earth Ceramics manufacture only Ceramic Glazed Wall / Floor tiles and not vitrified tiles.
- e) During the year 1999-2000 there was no sale of vitrified tiles by SPL. As such the figures are not at all comparable. Further, SPL's realization per MT increased mainly in value added products in glazed tiles segment while the case has been filed only for vitrified tiles. The irrelevance and mischievousness of the contention made by the importers is obvious.
- f) The increase in production capacity during the period of investigation is mainly because of additional floor tiles capacity put up at Kadi plant at Gujarat. In this case, we are concerned only with vitrified tiles.
- g) There was no production loss of vitrified tiles because of plant/equipment maintenance and upgradation.

- h) There is no loss of production of vitrified tiles because of overhauling of diesel generating sets as SPL had enough standby generation capacity to run the particular unit of vitrified tiles.
- i) The earthquake in Gujarat in the month of January 2001 had no effect on production of vitrified tiles as the plant for the same is located in Haryana. The importers have deliberately and knowingly ignored this fact with a view to confuse the issues.
- j) As already mentioned above, the commencement of production of vitrified tiles was in March, 2000. The complainant has wrongly taken the commencement of production in November 2000. This is misrepresentation of facts and there is no concealing of facts by SPL as has been alleged.
- k) The increase in total income during the first quarter of 2001-02 compared to corresponding quarter of previous year was not only because of vitrified tiles sales but also the sales of floor tiles of around Rs. *** lacs from the new commissioned floor tiles plant at Kadi in November 2000.
- l) The importers/exporters have referred time and again to figures which do not pertain to the production and sale of vitrified tiles and are confusing with production of wall and floor tiles in SPL plants. Thus, there is no relevance of adjustment of profits in view of the above. The growth of exports of SPL is on account of growth in wall and floor tiles exports.
- m) It is apparent from the above that all the contentions of the importers are based on misrepresentation, completely wrong interpretation of facts, figures and Anti-dumping

Rules and therefore, has no substance in relation to the period of investigation for vitrified tiles.

- n) HRJ manufactures Wall & Floor tiles in addition to the Vitrified Tiles. The Company has 4 plants in various parts of the country. The achievement shown in the Director's Report are combined achievement and not necessarily only because of vitrified tiles. The details regarding vitrified tiles have already been submitted separately.
- o) HRJ has been continuously adding capacity in last 2 years and therefore production has been increasing due to increase in the installed capacity.
- p) The capacities are added to achieve higher economy of scale particularly in a capital intensive industry. Again the total capacity as mentioned in the Balance Sheet cannot be compared as it comprises of Wall, Floor & Vitrified tiles and therefore is not any indicator.
- q) It is admitted fact that the Thane factory of HRJ is one of the oldest factory of the Company and outdated both in terms of technology as well as product mix. The Thane factory does not manufacture Vitrified Tiles.
- r) Anti-dumping Rules clearly provide that a proper application has to be filed by or on behalf of the domestic industry which accounts for at least 25% of the domestic production. The fact that some of the companies have not expressly supported the application is of no consequence either legally or in an economic sense. The conditions required for an application to form a valid application have been meticulously fulfilled by the petitioners.

s) The Petitioners are using state-of-the-art Italian technology for producing tiles and the claim is also evidenced from the capital expenditure. Indian industry has been continuously making investment & up-gradation of their manufacturing capabilities. HRJ spent an amount of Rs. *** Crores in last 4 years. The vitrified tiles factory of HRJ has been set up using the best of the plant & machinery and technology available in the world. The Italian technology for vitrified tiles is undisputedly acknowledged as the best in the world. The plant of HRJ has been supplied by SACMI of Italy, the major supplier of vitrified tiles plant in the world.

t) Vitrified tiles manufactured by HRJ have been very well accepted as can be seen by the fact that HRJ has received the PSB Certification from Singapore and Balogne Certificate from Italy. Therefore calling their tiles as inferior is totally misleading. In fact HRJ manufactures a high 70% of first quality Vitrified tiles. HRJ products are as good as the best products available in the world and it now exports to countries in Europe, Middle East and Far East.

u) The Petitioners (HRJ) have not resorted to any sale on Run of Kiln basis. The allegation is strongly objected and also merits a case of defamation. However, the importers should be asked to produce evidence for such a claim.

v) The tiles being marketed by HRJ as Porselano is indeed Vitrified Porcelain tiles contrary to the claim and due to total ignorance of the importers.

w) It is strange and shocking to see the argument of the importers that duty should not be imposed in consumer interest. The major exporter from UAE namely RAK Ceramics has itself admitted that they have been supplying 3rd and 4th quality tiles to India. Consumer interest cannot

be furthered by bringing 3rd & 4th quality products. Majority of imports are of 4th quality as admitted by RAK Ceramics in their submission and therefore the importers are misleading by making false claim of bringing exclusive/outstanding products.

E. EXAMINATION OF THE ISSUES RAISED

6. The foregoing submissions made by the exporters, importers, petitioner and other interested parties, to the extent these are relevant as per Rules and to extent these have a bearing upon the case, have been examined and considered and have been dealt with at appropriate places in the notification.

F. PRODUCT UNDER CONSIDERATION & SCOPE OF INVESTIGATION

7. The product under consideration claimed by the petitioners and mentioned in the Initiation Notification is “Unglazed tiles in polished or unpolished finish and Glazed Porcelain/Ceramic tiles both with less than 3% water absorption(commonly known as Vitrified Tiles/Porcelain tiles)” originating in or exported from subject countries. Vitrified/Porcelain tiles are glazed and unglazed tiles and are used primarily for coverings for floors as well as on walls. These tiles are used in buildings, homes, restaurants, cinema halls, airports, swimming pools, railway stations etc..

Petitioners have claimed that all types of unglazed tiles are classified in chapter heading 69.07. However, unglazed tiles are also being imported under Chapter heading 69.14, as other articles of porcelain. In addition, glazed porcelain tiles are being imported under Chapter heading 69.14 with various descriptions like G.P. Tiles, Porcelain Tiles, Gres Porcelanato Tiles, Porcelain Vitrified Tiles, etc. It has further been stated that the Glazed Porcelain Tiles, being imported under Chapter heading 69.14 are substitutable with the unglazed tiles of Chapter

Heading 69.07 in terms of properties, uses, functions, distribution channels etc. Petitioners have further submitted that Glazed Porcelain Tiles are erroneously being classified under Chapter Heading 69.14 by many importers. These products are rightly classifiable under Chapter Heading 69.08 as Glazed Tiles. Therefore, petitioners requested that the investigations be carried out against the product under consideration irrespective of the classification under which they are being imported. Customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

However, the domestic industry clarified to the Authority that the description in their application as well as the Initiation Notification does not cover industrial tiles even though the same are produced by the process of vitrification. They, therefore, requested that industrial vitrified tiles may be excluded from the scope of the present investigation as the same are not competing or substitutable with the allegedly dumped imports. On an examination of the material available, the Authority accepts the contention of the domestic industry and clarifies that the vitrified industrial tiles are not covered in scope of investigation.

G. LIKE ARTICLE

8. (a) Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules specifies that “Like Articles” means an article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination.
- (b) The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. Therefore, Vitrified/Porcelain tiles produced by the petitioners and imported from subject countries should be treated as ‘like articles’ in accordance with the Anti-dumping Rules.

(c) The exporters/importers have argued that the tiles imported by them are different in quality. However, no evidence has been adduced by them to indicate that the imported tiles are not substituting the domestically produced tiles either technically or commercially. The Authority notes that the vitrified tiles produced by the domestic industry has characteristics which are similar to those of the tiles imported from the subject countries. The channels of distribution, end-use, etc., also indicate that the imported tiles are like articles to the product under consideration.

(d) In view of the above, the Authority holds that Vitrified/Porcelain tiles produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are 'Like Articles' within the meaning of the Rules.

H. DOMESTIC INDUSTRY

9. The petition has been filed by M/s SPL Ltd., M/s H&R Johnson India Ltd. and M/s Murudeshwar Ceramics Ltd. The petitioners have claimed that they account for almost 60% of the total Indian production in terms of sq. mtrs. of the subject goods. It has been argued that the petitioners do not have the standing to file the application as the production of many other producers of tiles has not been taken into consideration for determining the standing criteria. The importers have specifically named few producers of tiles in support of their contention. The Authority has examined the contentions made by the importers in this regard as well as the evidence available on record. The producers referred to by the importers are not producing vitrified/porcelain tiles i.e., ceramic tiles with less than 3% water absorption and therefore, the question of inclusion of their production for the purpose of standing, does not arise. It has also been mentioned that there are several small scale producers of tiles whose production has also not been accounted for. The Authority hereby clarifies that under the Anti Dumping Rules, the Authority is required to take into account only the production

of the product under consideration. In the instant case, the scope of investigation is restricted only to vitrified tiles as defined under the product under consideration, and the standing criteria for the petitioners are adequately satisfied on the basis of the total production of the product under consideration in the country.

I. **DUMPING**

Normal Value

10. Under Section 9A(1)(C) normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in

accordance with the rules made under sub-section (6)”;

Separate provisions have been made in the Anti Dumping Rules for non market economy countries vide amendments notified on 15.07.1999 and 31.05.2001.

CHINA PR

11. The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). However, none of the exporters from China responded to the Authority in the prescribed questionnaire format nor have they provided adequate information. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from China has cooperated with the Authority as envisaged under the Rules. The domestic industry has furnished information with regard to the normal value in China based on the constructed cost of production. In view of non-cooperation from the exporters from China, the Authority has determined normal value in China on the basis of the constructed cost of production.

Export Price

12. None of the exporters from China has cooperated with the Authority by providing sufficient and complete information with regard to export volume and prices. Large exports of subject goods from China have started very recently and the data are not available from DGCI&S. In view of above, the data has been compiled by the domestic industry from secondary sources. Further adjustments has been given on account of freight, marine insurance, commission, port handling etc., to arrive at net export price on the basis of evidence provided by domestic industry.

Dumping Margin

The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin as laid down in the Custom Tariff Act and the Anti Dumping Rules are elaborated in Annexure I to the Rules. The dumping margin for exports of the subject goods from China comes to 247 % of the export price.

UAE

13. None of the exporters except M/s RAK Ceramics, has provided information in the prescribed questionnaire format.

As regards M/s RAK Ceramics, the domestic industry has made their submissions as follows:

- that the submissions made by the said exporter cannot be taken cognizance of in the absence of a proper non-confidential version of the exporter's response to the questionnaire. Further, the exporter has not bothered even to give non-confidential version or the indexed form of crucial appendices such as Appendices 4, 5, 6, 8, 9 and 10. In effect, the domestic industry has been deliberately blocked by the exporter from commenting on the price structure, total sales, adjustments etc. claimed by the exporter. The information submitted by the exporter cannot be accepted in the absence of proper non-confidential version. Therefore, the response of the exporter needs to be summarily rejected until they fulfill their legal obligations.
- The exporter has mentioned that the models sold to India are different from the models sold within UAE and to other countries. However, it appears that no specifications have been provided to establish, on the basis of technical parameters, as to how the models are different. The submissions have therefore been made on the basis of self-

serving statements and analysis. It is a well-settled principle of anti-dumping that physical differences are allowed to be adjusted only on the basis of the differences in cost which can be attributed to such established differences. Mere statements, conjectures and surmises are not sufficient to classify the products in a manner only to avoid anti-dumping duties. Further, the claims made by the exporter are contradictory. If the sales are to the end-users, where is the question of claiming quantity discount. The exporter has not given the Sales Arrangement as required under Para 'C' itself. Therefore, the information submitted by the exporter needs to be rejected as incomplete and unreliable.

- Under the anti-dumping laws and practice, adjustment on account of quality can be permitted only if the same can be demonstrated by physical attributes. Such claims cannot be permitted on account of differential price realization. The exporter has also not given the details of the actual credit advanced and has combined the domestic sales as well sales to other countries.
- The cost method adopted by RAK is highly objectionable and not sustainable because the cost of the product is the same irrespective of the grade. It is preposterous to suggest that the cost of the product is dependant upon the sales realization, whatever is the grade. Further, RAK itself has admitted that it does not have any cost accounting system and as and when required, "indicative cost" are made. In the same breath they state that there are no material differences between the production cost data supplied in reply to the questionnaire and in the cost data normally determined by using the Accounting System.

14. The above issues have been carefully examined by the Authority. The Authority finds considerable merit in the arguments advanced by the domestic industry. It has been noticed that the information required in the non-confidential

version has not been provided as pointed out by the domestic industry. The Authority also notes that the basis of gradation of different types of subject goods has not been brought out which makes it difficult to make proper comparison to carry out the dumping and injury margin analysis. The Authority also notes that the exporter has not given any cogent reasons for considering different costs for different grades of tiles.

In view of the above, the Authority has decided to ignore the information submitted by M/s RAK Ceramics and other exporters from UAE. The preliminary determination is therefore, made on the basis of the best information available on record.

15. Based on the above, the dumping margin for all exporters from UAE has been worked out as 148% of export price.

J. INJURY & CAUSAL LINK

16. Analysis of injury to the domestic industry has been done on the basis of the information available on record and the verification done by the officials of the Directorate General of Anti-dumping & Allied Duties. The following parameters have been analysed for the purpose of assessment of injury to the domestic industry:

Sales Volume & Value

The domestic industry claimed that the vitrified tiles industry is not very old in India. It was precisely when the industry was hoping to come out of the red in the last financial year, dumping from the subject countries resulted in increase in losses despite some improvement in sales volume and marginal increase in sales prices over the last two years. The Authority observes that there is an increase in the sales volume as well as sales value over the last two years. The unit price realization has also gone

up by about *** % in the period of investigation over the previous year but these increases have to be judged in the context of the additional capacities that had been created during this period and the extent of dumping, landed values vis-à-vis the selling prices of the domestic industry and the return on investment made by the domestic industry.

Market share of the imports from China and UAE

An examination of the import data for the subject goods would indicate that the imports (as a percent of the total imports) from the subject countries namely, China and UAE account for about 71% during the period of investigation.

Year	Imports from subject countries (Sq mtrs.)	Total Imports	% share
1998-99	0.00	121.00	0.00%
1999-2000	0.00	8.22	0.00%
April 2000-March 2001	119570.00	169246.70	70.65%

The Authority being aware that the imports of the subject goods were restricted in the years 1998-1999 and 1999-2000, decided to carry out an *inter se* trend analysis within the period of investigation. An examination of the import figures indicates that the imports from the subject countries have risen drastically in the second half of the period of investigation as compared to the first half. Of the total imports from the subject countries made during 2000-2001 i.e., the period of investigation, only 6.42% came during the first half while 93.58% was imported in the second half. Thus, it is clear that the imports from the subject countries show an alarming increasing trend within the period of investigation. There is an increase of over fifteen times in imports in the second half as compared to the first half of the

period of investigation. The Authority notes that the total imports also show a similar trend over during the very first year of opening up of imports but the change is not as drastic and marked as in the case of the subject countries. The rate of growth of imports within the period of investigation is a sufficient indicator of injury to the domestic industry. This fact has also to be viewed in the context of the abnormally low prices from the subject countries.

Particulars	1st Half		2nd Half		Total for 2000-2001	
	Qty(in Sq mtr)	Value(in Rs)	Qty(in Sq mtr)	Value(in Rs)	Qty(in Sq mtr)	Value(in Rs)
Subject Countries	7681	2870228	111889	23275570	119570	26145798
Other Countries	12999	3709046	36677	11722513	49677	15431559
Grand Total	20681	6579274	148567	34998083	169247	41577357
% share of imports						
From Subject Countries	6.42%	10.98%	93.58%	89.02%	100.00%	100.00%
From Other Countries	26.17%	24.04%	73.83%	75.96%	100.00%	100.00%
Total	12.22%	15.82%	87.78%	84.18%	100.00%	100.00%

Market Share of Imports from Subject Countries (% of Total Demand)

The Authority has calculated the total demand in the country by adding the total imports to the sales of the entire domestic industry including the petitioners as well as other producers of the product under consideration. The Authority notes that the imports from the subject countries could acquire a market share

of 3.66% of the total demand in a very short period of one year. Considering that vitrified tiles are in the nature of consumer goods, a market share of 3.66% clearly constitutes a significant proportion. If only the second half of the period of investigation is considered, the market share of dumped imports will be much higher. Moreover, the share of imports from the subject countries could be much more as the current estimates are only from select ports.

Year	Imports from subject countries (Sq mtrs)	Total Demand	% share
1998-1999	0.00	1884870	0.00%
1999-2000	0.00	2372081	0.00%
April 00/Mar 2001	119570	3262558	3.66%

Production & Lower Capacity Utilization

It has been stated by the domestic industry that the demand for the subject goods has grown in the country at a healthy rate and that its use over the conventional floor and wall coverings is steadily catching up. It has further been claimed that despite the existence of a growing market, their losses have gone up due to indiscriminate dumping by the subject countries. The Authority observes that the capacity utilization by the domestic industry in terms of square meters has gone up over the years. The domestic industry has argued that capacity utilization as a factor of injury cannot be of much significance in a product like vitrified tiles as the same would vary significantly depending upon the product mix of the tiles of different sizes being produced during a particular period. Thus, capacity utilization is not being considered as a valid indicator of the health of the industry for a

product like tiles where the installed capacity is also a variable depending upon various factors.

Selling Price / Profitability

The domestic industry has stated that they have made substantial investments and was trying to establish itself in the last two to three years. It has further been argued that the incidence of dumping to such a large extent has inflicted considerable injury to the domestic industry and their losses have increased at a time when the domestic industry was hoping to get out of the loss making situation. The Authority notes that the domestic industry as a whole had negative returns on their investments. It is also noted that MCL which is making some nominal profits has also not been able to recover a reasonable return on its capital employed. Their per unit profit in absolute terms for the vitrified tiles has also come down in the period of investigation over the preceding period.

Year	Sales Value (Rs. in lakhs)	Cost of Sales (Rs. in lakhs)	Profit/Unit
1998-1999	***	***	***
1999-2000	***	***	***
April 2000-March 2001	***	***	***

Price Undercutting

It has been claimed that dumping by China and UAE has had a significant impact on the net sales realization of the domestic industry for the subject goods. To hold on to its market share, the petitioners had to compete with low priced and dumped imports of subject goods from China & UAE. The landed value of the dumped imports also indicates that there is serious price under-cutting taking place.

	China (In Rs.)	UAE (In Rs.)
Average Selling Price of Indigenous Product (Excluding Excise Duty)	100.00	100.00
Landed Value of Imported product (CIF + Basic Customs Duty)	42.56	65.63
Extent of Price Undercutting	57.44	34.37

(In Rupees)

Price Underselling:

The Authority has also examined the claim of the domestic industry that the domestic industry is suffering on account of losses or abnormally low return on their investments by different units. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of injury. The Authority has worked out the Non-Injurious Price for the product under consideration and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant level of incidence of price underselling causing injury to the domestic industry. Examination of the available evidence also shows that the domestic industry as a whole has suffered losses on its sales of vitrified tiles. Even the unit which has

made some profits has not been able to recover a fair and reasonable return on its investments.

Inventories and Stocks

The analysis of the stocks show that there is an increase in stocks to the extent of about 14% at the end of the year 2000-2001 as compared to the previous year.

The fact of price underselling, extent of price undercutting, changes in the market share and the profitability/ROI parameters clearly indicate that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation caused by dumping from the subject countries.

K. CAUSAL LINK

17. In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:-

- (i) Imports of subject goods from China & UAE at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to un-remunerative level which has resulted in a situation of price undercutting in the Indian market.
- (ii) The imports from China & UAE suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable return from the sale of subject goods in India.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

18. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the petitioner companies and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the petitioner companies. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the petitioner companies and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject material. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

19. To ascertain the extent of anti-dumping duty necessary to remove the injury to the petitioner companies, the Authority has relied upon non - injurious selling price of subject goods in India by considering the optimum cost of production at optimum level of capacity utilisation for the petitioner companies.

20. Injury caused to the domestic industry from factors other than dumping, if any, have not been considered while recommending the amount of Anti-Dumping Duty necessary to remove the injury to the domestic industry caused by dumped imports.

21. The Authority does not recommend restriction on imports or supplies from any particular source, and therefore, availability of subject goods to the consumers would not be affected in the event of imposition of Anti-Dumping Duty.

M. CONCLUSIONS:

22. After considering the foregoing the Authority concludes that:-

- (a) Subject goods originating in or exported from UAE and China have been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- (b) The Indian industry has suffered material injury ;
- (c) The injury has been caused cumulatively by the imports from the subject countries.

23. It is considered necessary to impose anti dumping duty, provisionally, pending final determination, on all imports of subject goods originating in or exported from UAE and China.

24. The Authority considered recommending the amount of Anti-Dumping Duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to domestic industry. The average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the non-injurious selling price of the petitioner companies, determined for the period of investigations. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. It is considered necessary to impose antidumping duty, provisionally, pending further investigation and final determination on all imports of subject goods originating in or exported from UAE and China.

25. Accordingly, the Authority recommends that provisional anti-dumping duties be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from UAE and China from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. The anti-dumping duty shall be the difference between US \$ 13.62 per square metre and the landed value of

all the imports of subject goods originating in or exported from China and UAE.

26. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

N. FURTHER PROCEDURE:

27. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be interested are being addressed separately by the Authority. They may make known their views, within forty days from the date of the dispatch of this letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.
- (c) The Authority would provide opportunity to all the interested parties for oral submissions to be rendered thereafter in writing.
- (d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- (e) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority